सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार
*" समय और सम्मान, दोनों बहुत कीमती होते हैं-
एक भी चला जाए तो लौटता नहीं ...!! "*
अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–143 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शुक्रवार 12 जून 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

19 का मैजिक नंबर अधूरा, शत्रुघ्न सिन्हा और प्रतिमा मंडल ने किया बगावत से इनकार

आलोक तिवारी / कोलकाता

बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब पार्टी का फोकस टीएमसी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को अपने पाले में लाने पर है। 'ऑपरेशन लोटस' के तहत दलबदल की कोशिशें तेज हो गई हैं।

क्या है 19 का मैजिक नंबर

दलबदल कानून से बचने के लिए भाजपा को टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से दो-तिहाई यानी 19 सांसदों का समर्थन चाहिए। टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बाईक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। बंगाल में भाजपा सरकार होने से उपचुनाव में ये सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं।

बागी गुट की कमान किसके हाथ

सूत्रों के मुताबिक 4 दशक तक ममता बनर्जी की साथी रहीं काकोली घोष दस्तीदार इस बागी गुट की मुखिया बताई जा रही हैं। उन्होंने विधानसभा नतीजों से पहले ही भाजपा नेतृत्व से संपर्क किया था। सुष्मिता देव और जादवपुर सांसद सयोनी घोष कोलकाता में सांसदों को जुटाने में लगी हैं।

भाजपा के रणनीतिकार

इस पूरे ऑपरेशन को असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और भाजपा महासचिव सुनील बंसल बैक-स्टेज से मैनेज कर रहे हैं।

ममता का डैमेज कंट्रोल, दो सांसदों ने किया इनकार

भाजपा का गणित फिलहाल कमजोर पड़ा है। आसनसोल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उनका नाम बिना पूछे लिस्ट में डाला गया है। उन्होंने टीएमसी के साथ रहने का व्हिप जारी किया। जयनगर सांसद प्रतिमा मंडल ने खबरों को झूठा बताया और हस्ताक्षरित पत्र दिखाने की चुनौती दी। इन दोनों के इनकार के बाद बागी गुट के पास 18 सांसद बचते हैं, जो मैजिक नंबर 19 से एक कम है।

20 सांसदों की लिस्ट वायरल

बागी गुट की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को 20 सांसदों की लिस्ट भेजने की खबरें थीं। इसमें काकोली घोष, यूसुफ पठान, देव, शताब्दी राय, रचना बनर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा और प्रतिमा मंडल जैसे नाम शामिल हैं।

टीएमसी में अंदरूनी खींचतान

लोकसभा में टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच विवाद की खबरें भी हैं। कल्याण बनर्जी ने ममता से कहा कि "अगर आप अभिषेक पर निर्भर रहना चाहती हैं तो मुझे छोड़ दीजिए"। हालांकि सूत्र मानते हैं कि कल्याण बनर्जी ममता का साथ नहीं छोड़ेंगे। बाबुल सुप्रियो टीएमसी में ही हैं क्योंकि भाजपा ने उनके लिए नो-एंट्री लगा रखी है। फिलहाल ममता बनर्जी के पास पार्टी बचाने का मौका है, लेकिन सियासी उठापटक जारी है।

संसदीय स्थायी समिति ने बीएसपी का किया दौरा

ब्लास्ट फर्नेस-8 और यूनिवर्सल रेल मिल का लिया जायजा, 260 मीटर लंबी रेल उत्पादन प्रक्रिया देखी

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

वाणिज्य संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों ने आज राज्यसभा सदस्य एवं समिति अध्यक्ष श्रीमती डोला सेन के नेतृत्व में सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र का संक्षिप्त दौरा किया।

राज्यसभा-लोकसभा सदस्यों ने लिया उत्पादन का जायजा

समिति में राज्यसभा सदस्य डॉ. संगीता बलवंत, धनंजय भीमराव महाडिक, सदानंद म्हालू सेठ तानावड़े, बिस्वजीत सिन्हा तथा लोकसभा सदस्य रमेश अवस्थी, आनंद भदौरिया, अतुल गर्ग, के. राजशेखर बसवराज हितनाल, डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले, संतोष पांडेय, डॉ. शिव पाल सिंह पटेल, आमरा राम, अनीता सुभदर्शिनी एवं गिरधारी यादव शामिल थे। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

एचआरडीसी में हुआ स्वागत और प्रस्तुतीकरण

संयंत्र पहुंचने पर मानव संसाधन विकास केंद्र में कार्यकारी निदेशक प्रभारी अजय कुमार चक्रवर्ती सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने समिति का स्वागत किया। उप प्रबंधक (जनसंपर्क) शालिनी चौरसिया ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उत्पादन इकाइयों, प्रमुख उत्पादों, तकनीकी विशेषताओं और सीएसआर गतिविधियों की जानकारी दी। सुरक्षा निर्देशों से भी अवगत कराया गया।

ब्लास्ट फर्नेस-8 और यूआरएम का निरीक्षण

समिति सदस्यों ने ब्लास्ट फर्नेस-8 में हॉट मेटल उत्पादन प्रक्रिया और यूनिवर्सल रेल मिल में विश्व की सबसे लंबी 260 मीटर रेलों के निर्माण एवं रोलिंग प्रक्रिया को निकट से देखा। सदस्यों ने उत्पादन प्रणाली, आधुनिक तकनीकी संचालन और गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्थाओं में विशेष रुचि दिखाई।

भ्रमण के बाद मानव संसाधन विकास केंद्र में समिति सदस्यों ने संयंत्र की कार्यप्रणाली और उत्पादन गतिविधियों को लेकर अपने अनुभव साझा किए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हैदराबाद में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट में शामिल

निवेशकों को दी नई औद्योगिक नीति की जानकारी, 8 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मिले

नई दृष्टिबिंदु / हैदराबाद

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने निवेशकों को छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति और निवेश संभावनाओं की जानकारी दी।

निवेश के लिए अनुकूल माहौल

मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण है। प्रक्रियाएं अब और अधिक सरल और पारदर्शी हो गई हैं। राज्य में उद्योग, अधोसंरचना, ऊर्जा, आईटी, खाद्य प्रसंस्करण और खनिज आधारित क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर हैं। उन्होंने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

8 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव

नई उद्योग नीति और निवेशक-अनुकूल फैसलों से राज्य को लगातार बड़े निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं। अब तक छत्तीसगढ़ को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं।

उद्योग समूहों से चर्चा

हैदराबाद में विभिन्न उद्योग समूहों और निवेशकों के साथ चर्चा हुई। निवेश की संभावनाओं पर मंथन किया गया। इससे पहले अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, जापान और दक्षिण कोरिया में भी निवेशक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री की निवेश प्रोत्साहन पहल से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों में छत्तीसगढ़ के प्रति आकर्षण बढ़ा है।

ओवर रेटिंग पर आबकारी विभाग सख्त, दो उप निरीक्षक निलंबित

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

शराब की अधिक दर पर बिक्री के मामलों में आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। रायपुर के फाफाडीह और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गंडई स्थित शराब दुकानों में ओवर रेटिंग पकड़े जाने पर दो आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित किया गया है।

फाफाडीह में 20 रुपये ज्यादा वसूली

राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल ने फाफाडीह विदेशी मदिरा दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच में विक्रेता अश्वन कुमार मेरिया द्वारा दो पाव ऑल सीजन गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की 480 रुपये की जगह 500 रुपये में बेचना पाया गया। उपभोक्ता से 20 रुपये अधिक वसूले गए। इस पर विक्रेता के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। लापरवाही पर क्षेत्र के आबकारी उप निरीक्षक कौशल किशोर सोनी को तत्काल निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय उड़नदस्ता रायपुर रहेगा।

गंडई में 10 रुपये ज्यादा लिए

उड़नदस्ता टीम ने गंडई की कम्पोजिट मदिरा दुकान का निरीक्षण किया। ग्राहक से जांच में पता चला कि विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर ने तीन पाव देशी मदिरा प्लेन 240 रुपये की जगह 250 रुपये में बेची। 10 रुपये अधिक वसूली पर विक्रेता के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज हुआ। कमजोर निगरानी और लापरवाही पर गंडई वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को निलंबित किया गया है। आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि शराब बिक्री में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

फाफाडीह और गंडई शराब दुकान में मिली गड़बड़ी, विक्रेताओं पर केस दर्ज

अवैध गुटका फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, 10 आरोपी गिरफ्तार

कुथरेल और अंडा में चल रहा था अवैध निर्माण, मशीनें और कच्चा माल जब्त

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

थाना अंडा और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने अवैध गुटका निर्माण की दो फैक्ट्रियों पर दबिश देकर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में कच्चा माल, मशीनें, पैकेजिंग सामग्री और तैयार गुटका जब्त किया गया।

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

पुलिस को सूचना मिली थी कि कुथरेल और अंडा क्षेत्र में बिना अनुमति के अवैध गुटका निर्माण और पैकेजिंग का काम चल रहा है। टीम ने दोनों स्थलों पर छापा मारा। जांच में अवैध रूप से गुटका बनाने की पुष्टि हुई।

आरोपी यूपी के निवासी

गिरफ्तार सभी 10 आरोपी उत्तर प्रदेश के बांदा, हरदोई, उन्नाव, कानपुर और फतेहपुर जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों में बिरेन्द्र तिवारी, सुभाष कुमार गौतम, सुनील कुमार राजपूत, करण राजपूत, राजू मस्ताना, राजकुमार यादव, रमेश कुमार निषाद, सतेन्द्र कुमार यादव, सोनू यादव और बसंत राजपूत शामिल हैं।

केस दर्ज, जांच जारी

थाना अंडा में अपराध क्रमांक 63/2026 और 64/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 3(5) और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार अवैध आर्थिक लाभ के लिए यह कारोबार चलाया जा रहा था।

जब्त सामग्री

पुलिस ने गुटका निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल, रसायन, मशीनें, पैकेजिंग सामग्री तथा तैयार और अर्द्धनिर्मित गुटका उत्पाद जब्त किए हैं।

पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों के निर्माण, भंडारण या बिक्री की सूचना तुरंत नजदीकी थाने या पुलिस कंट्रोल रूम को दें।

नेहरू नगर के सूने मकान में लाखों की चोरी, अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

मुख्य आरोपी सहित 6 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने किया सोना-चांदी, नगदी और वाहन जब्त

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

थाना सुपेला पुलिस ने नेहरू नगर पश्चिम के सूने मकान में हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने-हीरे और चांदी के आभूषण, नगदी, वाहन और औजार जब्त किए गए।

धार्मिक कार्यक्रम में गए थे, पीछे से हुई चोरी

प्रार्थी विनय कुमार अग्रवाल 4 मई को परिवार सहित घर में ताला लगाकर धार्मिक कार्यक्रम में गए थे। 5 मई को लौटने पर घर का ताला और अलमारी के लॉक टूटे मिले। अज्ञात चोरों ने सोना, हीरा, चांदी के आभूषण और करीब 3,40,000 रुपये नगद चोरी कर लिए। थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 624/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई।

रेकी कर देते थे वारदात को अंजाम

जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी हारिम और मोहम्मद नासिर हुसैन ने सहयोगियों के साथ मिलकर सूने मकानों की रेकी कर चोरी की। आरोपियों ने चोरी के गहने मेरठ के एक ज्वेलर्स को बेचे और रकम आपस में बांट ली।

कई राज्यों में दबिश, 6 गिरफ्तार

पुलिस टीम ने मेरठ और नई दिल्ली में दबिश देकर हारिम, मोहम्मद नासिर हुसैन, मोहम्मद कासिम, सलीम, मोहम्मद बिलाल और दिन मोहम्मद को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी के सोने-चांदी के आभूषण, नगदी, जुपिटर और सेल्टोस वाहन, मोबाइल फोन और ताला तोड़ने के औजार बरामद हुए। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

पुलिस की भूमिका सराहनीय, दुर्ग पुलिस की अपील

कार्रवाई में थाना सुपेला के निरीक्षक विजय कुमार यादव, उप निरीक्षक धनेश्वर साहू, प्रधान आरक्षक योगेश पाण्डेय और विशेष टीम की सराहनीय भूमिका रही। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि घर लंबे समय तक सूना छोड़ने पर पड़ोसियों को सूचित करें। सुरक्षा उपकरण और सीसीटीवी कैमरे लगाएं। संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

रेडियो एक्टिव सामान के नाम पर 3.08 करोड़ की ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर। थाना गांधीनगर पुलिस ने षड़यंत्रपूर्वक ठगी करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी दुर्लभ सामान और रेडियो एक्टिव पैकिंग बेचने के नाम पर प्रार्थी से 3,08,78,000 रुपये की ठगी कर चुके थे।

प्रार्थी करमबेल कच्छप निवासी गंगापुरखुर्द ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2024 के बीच आरोपियों ने फर्जी रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन दस्तावेज दिखाकर पुरानी दुर्लभ वस्तु और रेडियो एक्टिव पैकिंग बेचने के नाम पर झांसा दिया। योजनाबद्ध तरीके से कुल 3,08,78,000 रुपये ठग लिए गए। थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 217/2026 धारा 318(4), 317(4), 111, 61(2), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देश पर साइबर सेल की तकनीकी मदद से दो पुलिस टीम पश्चिम बंगाल और उत्तरप्रदेश भेजी गई। आरोपी बल्ला रामा कृष्णा और संजय कुमार बिंद को रेलवे सुरक्षा बल बिलासपुर की टीम के साथ पटना रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। तीसरा आरोपी बाबूलाल राजभर बनारस से गिरफ्तार हुआ।

विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं के मध्य समन्वय विषयक पर हुआ सेमीनार

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 से संबंधित प्रकरणों के सौहादर्पूर्ण एवं त्वरित निराकरण हेतु दिनांक 18 जुलाई 2026 को आयोजित की जाने वाली विशेष लोक अदालत के सफल संचालन एवं व्यापक जन-जागरूकता के उद्देश्य से आज नवीन सभागार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में एक सेमीनार का आयोजन किया गया।

सेमीनार में जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशगण, जिला अधिवक्ता संघ, दुर्ग के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण, जिला दुर्ग से चयनित स्टेट बार काउंसिल के सदस्य, न्यायालयीन अधिकारीगण तथा कमर्चारीगण ने सहभागिता की। कार्यक्रम में विशेष लोक अदालत के उद्देश्य, महत्व एवं उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की गई तथा धारा 138 से संबंधित प्रकरणों के शीघ्र, सुलभ एवं सौहादर्पूर्ण निराकरण में लोक अदालत की प्रभावी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम के वक्ताओं ने विषय वस्तु पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए अधिवक्ताओं से विशेष लोक अदालत के संबंध में अपने-अपने पक्षकारों को जागरूक करने तथा समझौता योग्य प्रकरणों को चिन्हांकित कर लोक अदालत के माध्यम से निराकरण हेतु प्रेरित करने का आग्रह किया।

अपने उद्बोधन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने कहा कि विशेष लोक अदालत न्याय को सरल, सुलभ एवं त्वरित रूप से जनसामान्य तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अधिवक्तागण से अधिकाधिक समझौता योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर विशेष लोक अदालत में प्रस्तुत कराने तथा पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों से अवगत कराने का आग्रह किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि न्यायपालिका एवं अधिवक्ता समुदाय के समन्वित प्रयासों से बड़ी संख्या में प्रकरणों का सौहादर्पूर्ण निराकरण संभव हो सकेगा।

जिला अधिवक्ता संघ, दुर्ग के अध्यक्ष ने भी अपने उद्बोधन में विशेष लोक अदालत की सफलता में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए सभी अधिवक्ताओं से सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने तथा अधिकाधिक उपयुक्त प्रकरणों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के सहयोग से पक्षकारों को त्वरित एवं प्रभावी न्याय प्राप्त होगा तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के बोझ को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

सेमीनार के दौरान न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं के मध्य विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तथा सभी प्रतिभागियों ने इसे जनहित एवं न्यायहित में एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम का वातावरण अत्यंत सकारात्मक एवं सहभागितापूर्ण रहा।

अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा उपस्थित सभी न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा आशा व्यक्त की गई कि दिनांक 18 जुलाई 2026 को आयोजित विशेष लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों का सौहादर्पूर्ण निराकरण कर न्याय सुलभता एवं त्वरित न्याय के उद्देश्य को प्रभावी रूप से साकार किया जा सकेगा।

खास खबर

विधायक देवेन्द्र यादव ने रक्तदान के लिए निस्वार्थ सेवा भाव समिति का किया सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

खुर्सीपार में प्रतिभाओं का समर कैंप का आयोजन 9 मई से 7 जून तक किया गया। जिसमें 700 बच्चों ने योग, फिजिकल ट्रेनिंग, कराटे, बॉक्सिंग, एथलेटिक, क्रिकेट और फुटबॉल आदि खेलों में भाग लिया। समापन समारोह का आयोजन खुर्सीपार स्थित श्री राम चौक दशहरा मैदान में विधायक देवेंद्र यादव के मुख्य अतिथि में किया गया। इस दौरान समाजसेवा एवं मानवता के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए निस्वार्थ सेवा भाव समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार को रक्तदान जागरूकता और रक्तदान सेवा के माध्यम से हजारों जरूरतमंदों के जीवन को नई आशा प्रदान करने हेतु सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जैन, प्रथम महापौर नीता लोधी, एमआईसी सदस्य लक्ष्मीपति राजू, ब्लॉक अध्यक्ष गुड्डू खान और विधायक प्रतिनिधि इंद्रजीत सिंह सेनी आदि मौजूद थे।

जनता की हर समस्या का होगा समाधान, अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश : विधायक देवेंद्र यादव

भिलाई। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सेक्टर-5 स्थित विधायक कार्यालय में विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों से भेंट-मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न वार्डो से पहुंचे लोगों ने पेयजल, बिजली, सड़क, नाली और जल निकासी से जुड़ी समस्याएं रखीं।

गर्मी में पेयजल-बिजली संकट पर जताई नाराजगी : नागरिकों ने गर्मी के मौसम में पर्याप्त पेयजल नहीं मिलने और कई क्षेत्रों में नलों से नियमित आपूर्ति न होने की शिकायत की। बार-बार बिजली कटौती और बिजली बिलों में वृद्धि को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जताई।

अधिकारियों से तत्काल चर्चा कर दिए निर्देश : विधायक देवेंद्र यादव ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से तत्काल चर्चा की। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निराकरण करने और जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: विधायक-विधायक ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक नागरिक को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर समस्याओं का त्वरित समाधान कराया जा रहा है। विधायक ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र के विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्राप्त सभी शिकायतों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। नागरिकों ने समस्याओं को गंभीरता से सुनने और त्वरित पहल पर संतोष जताया।

विधायक ललित चंद्राकर ने किया 1.95 लाख की लागत से लगे स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण

नेवई-उतई मुख्य मार्ग पर 141 डिजाइनर पोल से जगमगाया 3 किमी का सफर

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नेवई से उतई मुख्य मार्ग पर नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3 किलोमीटर तक लगाए गए 141 डिजाइनर पोल का विधायक ललित चंद्राकर ने मुख्यातिथि के रूप में स्विच बटन दबाकर विधिवत लोकार्पण किया। इन पोल की कुल लागत राशि ?1.95 लाख है।

लोकार्पण अवसर पर मुख्यातिथि विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि नेवई-उतई मुख्य मार्ग पर डिजाइनर स्ट्रीट लाइट लगने से अब रात में आवागमन करने में सुविधा होगी। छात्र-छात्राओं, कामकाजी महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को अब अंधेरे की वजह से परेशानी नहीं होगी। सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी और असामाजिक तत्वों पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता को बेहतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं।

श्री चंद्राकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने के लिए दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। डबल इंजन सरकार में शहर हो या गांव, हर क्षेत्र का समग्र विकास हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने निगम प्रशासन और रिसाली के जनप्रतिनिधियों की सराहना करते हुए कहा कि जनभागीदारी से ही विकास को गति मिलती है। विधायक ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में रिसाली,नेवई, उतई सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा।

इस अवसर पर रिसाली निगम महापौर श्रीमती शशि सिन्हा, सभापति केशव बंछोर, नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू, एमआईसी सदस्य सनीर साहू, मरोदा पुरैना मंडल अध्यक्ष राजू जंघेल, रिसाली मंडल अध्यक्ष अनुपम साहू, महामंत्री नरेन्द्र निर्मलकर, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनोज साहू, महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती शिखा तिवारी, रिसाली निगम विधायक प्रतिनिधि गोविन्द साहू, पार्षदगण राहुल राय, धर्मेन्द्र भगत, हरीश नायक, विक्की चन्द्राकर, विधि यादव, परमेश्वर, चंद्रप्रकाश निगम, श्रीमती सविता धवज, श्रीमती रमा साहू, श्रीमती ममता नवीन सिन्हा, श्रीमती ईश्वरी साहू, श्रीमती सीमा साहू, श्रीमती सोनिया देवांगन सहित भाजपा कार्यकर्ता, निगम के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में देवतुल्य नागरिकगण उपस्थित रहे।

दुर्ग शहर में महाराजा चौक से बोरसी चौक तक अतिक्रमण की भेंट चढ़ रही 25 फीट सर्विस रोड

रहवासियों ने किया जोरदार प्रदर्शन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

महाराजा चौक से बोरसी चौक तक प्रस्तावित 80 फीट सड़क चौड़ीकरण परियोजना के बीच 25 फीट चौड़ी सर्विस रोड अतिक्रमण की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। क्षेत्र के रहवासियों का आरोप है कि राजस्व अभिलेखों और अनुमोदित ले-आउट के अनुसार सड़क के दोनों ओर सर्विस रोड का प्रावधान था, लेकिन अवैध कब्जों के कारण वर्तमान में सर्विस रोड एक तरफ ही सीमित होकर रह गई है।

तालाब के नीचे स्थित बस्ती के लोगों का कहना है कि लगभग 800 से 1000 लोगों का प्रतिदिन इसी मार्ग से आवागमन होता है। सर्विस रोड के संकरे होने और कई स्थानों पर अतिक्रमण होने के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार अब तक कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

रहवासियों ने बताया कि सड़क को पुनः 80 फीट चौड़ा करने के लिए तालाब की विपरीत दिशा में रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जा रहा है। वॉल के नीचे 25 फीट चौड़े सर्विस रोड का प्रावधान पूर्व से मौजूद है, किंतु अतिक्रमण के कारण उसका वास्तविक स्वरूप समाप्त होता जा रहा है। उनका आरोप है कि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित ले-आउट में दर्शाई गई सीमा तक सर्विस रोड उपलब्ध नहीं कराई गई है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस संबंध में मंत्री, जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन और पत्र सौंपे जा चुके हैं। लगातार पत्राचार के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराज रहवासियों ने सर्विस रोड की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से अविलंब अतिक्रमण हटाकर दोनों ओर 25 फीट चौड़ी सर्विस रोड उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सक्षम न्यायालय की शरण लेने को बाध्य होंगे। रहवासियों का कहना है कि सुरक्षित आवागमन और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अतिक्रमण हटाना और स्वीकृत ले-आउट के अनुसार सर्विस रोड का निर्माण कराना आवश्यक है। अब क्षेत्र की जनता की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

विधायक रिकेश का प्रयास : वैशाली नगर में 5.25 करोड़ के विकास कार्यो को मिली मंजूरी

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नगरीय स्लम स्वास्थ्य योजना : क्षेत्र के हजारों नागरिकों को बेहतर आवागमन, जल निकासी और मूलभूत सुविधाओं का मिलेगा लाभ

वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। क्षेत्रीय विधायक रिकेश सेन के लगातार प्रयासों और जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने का परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्रियदर्शिनी परिसर पश्चिम क्षेत्र में विभिन्न आधारभूत विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ 25 लाख 47 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति से क्षेत्र के हजारों नागरिकों को बेहतर आवागमन, जल निकासी और मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

वर्षो पुरानी मांग होगी पूरी

स्वीकृत परियोजना के तहत प्रियदर्शिनी परिसर पश्चिम में पहुंच मार्ग निर्माण, नाली निर्माण और विद्युतीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य कराए जाएंगे। लंबे समय से क्षेत्रवासी इन सुविधाओं की मांग कर रहे थे, जिसे विधायक रिकेश सेन ने लगातार शासन स्तर पर उठाया। अब स्वीकृति मिलने के बाद इन कार्यों के पूरा होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, जलभराव की समस्या में

कमी आएगी और क्षेत्र की आधारभूत संरचना मजबूत होगी।

विकास के लिए लगातार सक्रिय रहे विधायक

क्षेत्र के विकास को लेकर विधायक रिकेश सेन लगातार राज्य शासन और संबंधित विभागों के संपर्क में रहे। उन्होंने क्षेत्र की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए प्रस्तावों को आगे बढ़ाया और शीघ्र स्वीकृति

के लिए लगातार प्रयास किए। उनकी पहल पर ही विकास कार्यों के लिए आवश्यक प्रस्ताव शासन तक पहुंचे और अंततः उन्हें मंजूरी मिल सकी।

राज्य सरकार और मंत्री का जताया आभार

विकास कार्यों की स्वीकृति मिलने पर विधायक रिकेश सेन ने राज्य सरकार तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की सकारात्मक सोच और जनहितकारी दृष्टिकोण के कारण वैशाली नगर क्षेत्र को यह महत्वपूर्ण सौगात मिली है। विधायक ने विश्वास जताया कि आगामी समय में भी क्षेत्र के विकास के लिए इसी तरह नई परियोजनाओं को स्वीकृति दिलाने का प्रयास जारी रहेगा।

क्षेत्रवासियों को मिलेगा सीधा लाभ

इन कार्यों के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित पहुंच मार्ग, बरसात के दौरान जलभराव की समस्या में राहत, आधुनिक नाली व्यवस्था, बेहतर स्ट्रीट लाइट और विद्युतीकरण से क्षेत्र की सौंदर्यता और आधारभूत ढांचे में सुधार होगा। हालिया स्वीकृति को क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

ई-चालान और लाइसेंस जैसे अन्य फीसों में जनता का हो रहा आर्थिक शोषण - धीरज बाकलीवाल

जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने किया आरटीओ कार्यालय का घेराव

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

बड़े वाहनों के ट्रांसफर शुल्क को 1000 से बढ़ाकर 2500 कर दिया गया है। कार के ट्रांसफर शुल्क को 600 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। लगातार ई चालान के नाम से जनता परेशान हो रही है। इन सभी परेशानियों को लेकर आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया व ज्ञापन देकर समस्याओं की निराकरण की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ो कांग्रेसियों ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। करीब एक घंटा जमीन में बैठकर जमकर नारेबाजी करते रहे उसके बाद परिवहन अधिकारी के आने के बाद उनको ज्ञापन सौंपा गया।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने कहा कि इन बढ़ी हुई दरों के कारण आम नागरिकों, मध्यम वर्गीय परिवारों, मजदूरों, किसानों एवं छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वाहनों के रजिस्ट्रेशन तथा अन्य परिवहन संबंधी कार्यों के नाम पर भी आम जनता से अत्यधिक राशि लिए जाने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिससे लोगों में विभाग के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। दुर्ग शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा लगातार की जा रही दंडात्मक कार्यवाही, अत्यधिक राशि के ई-चालान तथा परिवहन संबंधी सेवाओं की बढ़ी हुई शुल्क दरों को लेकर आम नागरिकों में व्यापक असंतोष व्याप्त है।

बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को जारी ई-चालानों की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती, जिसके कारण उन्हें अनावश्यक आर्थिक एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन हस्तांतरण एवं अन्य परिवहन सेवाओं की बढ़ी हुई शुल्क दरों ने आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है।

वर्तमान में विभिन्न परिवहन सेवाओं के शुल्क में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई है, जिससे आम नागरिकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उदाहरण स्वरूप- मोटरसाइकिल के नए रजिस्ट्रेशन का शुल्क 150 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। कार के नए रजिस्ट्रेशन का शुल्क 500 तक कर दिया गया है। पुरानी मोटरसाइकिल के वेरिफिकेशन/मार्किंग शुल्क को 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। पुरानी कार के मार्किंग शुल्क को 500 कर दिया गया है। ट्रक के मार्किंग शुल्क के नाम पर 1000 तक लिए जा रहे हैं। पुरानी मोटरसाइकिल के ट्रांसफर शुल्क को 400 से और अधिक बढ़ा दी गई है।

उपरोक्त मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो कांग्रेस पार्टी आम जनता के हितों की रक्षा हेतु उनके साथ खड़ी होकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन एवं उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन एवं संबंधित विभाग की होगी।

आज के प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के साथ मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष अलताफ अहमद, नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रायसिंह ढिकोला, प्रवक्ता नासिर खोखर, सुशील भारद्वाज ब्लॉक अध्यक्ष मनीष बघेल, आनंद कपूर ताम्रकार, गुरदीप सिंह भाटिया, दुष्यंत देवांगन,गौरव उमरे, संजय बत्रा, राजकुमार नारायणी,देव सिन्हा,अनीस रजा,इशाक अली, कल्याण सिंह ठाकुर, दीपक सिन्हा, मनोज सिन्हा, पूर्व पार्षद बृजेन्द्र भारद्वाज, रत्ना नरमदेव, अनिल राव, खुर्शीद अहमद, ईश्वर साहू, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिशिर कसार, अब्दुल वहीद चौहान, चंद्रभान गभने, अली असगर, चिराग शर्मा, नवाब खान, प्रकाश सिवणकर, अंश चतुर्वेदी, आयुष शर्मा, मोहित वालदे सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे।

स्वस्थ छत्तीसगढ़ की नई रूपरेखा तैयार, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और डिजिटल हेल्थ पर दिया जोर

स्वस्थ छत्तीसगढ़ परामर्श में विशेषज्ञों ने सुझाए ठोस कदम ; स्वास्थ्य तंत्र सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन और तकनीक आधारित सेवाओं को मिलेगी नई गति

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी, सुलभ और जनकेंद्रित बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने नई पहल शुरू की है। इसी कड़ी में गुरुवार को स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर में आयोजित स्वस्थ छत्तीसगढ़ परामर्श में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने राज्य की स्वास्थ्य चुनौतियों और संभावनाओं पर मंथन किया। बैठक में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच, स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में चिन्हित किया गया।

बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया ने की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने तथा सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार पर काम किया जा रहा है। इस दौरान आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं संजीव कुमार झा भी उपस्थित थे। बैठक में विशेषज्ञों ने बताया कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान, नियमित जांच, सुरक्षित प्रसव और प्रभावी रेफरल व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। विशेष रूप से दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उपायों पर चर्चा की गई।

सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों के पास बर्थ वेटिंग होम स्थापित करने, आपातकालीन परिवहन सेवाओं को और मजबूत करने तथा प्रसूति सेवाओं से जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों के कौशल विकास पर भी जोर दिया गया। बाल स्वास्थ्य से जुड़े सत्रों में नवजात मृत्यु, निमोनिया, डायरिया और कुपोषण जैसी चुनौतियों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने जन्म के तुरंत बाद स्तनपान, नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने को महत्वपूर्ण बताया।

बैठक में यह भी बताया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आंकड़ों और तकनीक का बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और जरूरत के अनुसार सेवाओं के विस्तार के लिए डेटा आधारित निर्णयों पर जोर दिया गया। दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और स्वास्थ्यकर्मियों को लंबे समय तक सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहन संबंधी उपायों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान की उपलब्धियों को भी साझा किया गया। बताया गया कि व्यापक स्वास्थ्य जांच, गांव-गांव तक पहुंच और तकनीक के उपयोग से बस्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में सकारात्मक परिणाम मिले हैं।

डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने ई-संजीवनी, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, अइलअ आधारित सेवाओं और ऑनलाइन रेफरल व्यवस्था के विस्तार को भविष्य की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताया। इससे मरीजों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। परामर्श के अंत में स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर व्यापक सहमति बनी। विशेषज्ञों ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने, मानव संसाधनों को मजबूत करने और डिजिटल तकनीकों के अधिक उपयोग से छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। बैठक से प्राप्त सुझावों के आधार पर राज्य के लिए एक सशक्त स्वास्थ्य रोडमैप तैयार किया जाएगा, जो बेहतर स्वास्थ्य संकेतकों और सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मार्गदर्शक बनेगा।

खास खबर

राज्यपाल डेका से लेखिका पूजा अग्रवाल की पुस्तक का किया विमोचन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका से लोक भवन में लेखिका श्रीमती पूजा अग्रवाल ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने उनकी स्वरचित कहानी संग्रह माटी के पंख का विमोचन किया। लेखिका ने राज्यपाल को पुस्तक की विषय-वस्तु से अवगत कराते हुए बताया कि यह कहानी संग्रह प्रकृति संरक्षण का संदेश देती है। राज्यपाल ने पुस्तक के विषय और उसके संदेश की सराहना करते हुए कहा कि प्रकृति के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने लेखिका पूजा अग्रवाल को उनके रचनात्मक प्रयास के लिए शुभकामनाएं दीं तथा पुस्तक के व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचने की कामना की।

राज्यपाल रमेन डेका से परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारियों ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से लोकभवन में छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के महानिदेशक सुब्रत साहू के नेतृत्व में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। राज्यपाल श्री डेका ने परिवीक्षाधीन अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि अपना कर्तव्य भली-भांति निभाते हुए देश और समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें और मानवीय संवेदनाओं के साथ कार्य करें। आम आदमी को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दें साथ ही अपने अधीनस्थों के प्रति भी संवेदनशील रहें।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सीआर प्रसन्ना, संचालक छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी टीसी महावर, प्रशिक्षण निदेशक प्रणव सिंह सहित परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी गोकुल आरके, वदथ्यवथ यशवंत नाइक एवं इशांत जायसवाल उपस्थित थे।

9 टन यूरिया जब्त, एक दुकान पर 21 दिन का प्रतिबंध

रायपुर। रायगढ़ जिले के पुसौर क्षेत्र में उर्वरक कारोबारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दुकान से 9 टन यूरिया जब्त किया है, जबकि दूसरी दुकान पर 21 दिनों के लिए विक्रय प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कार्रवाई संयुक्त जांच दल की छापेमारी में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के बाद की गई। जांच के दौरान अग्रवाल खाद भंडार में लगभग 9 टन यूरिया का भौतिक भंडारण पाया गया, लेकिन स्टॉक रजिस्टर और पीओएस मशीन में उसकी कोई प्रविष्टि नहीं मिली। अभिलेखों और वास्तविक स्टॉक में अंतर पाए जाने पर पूरे खाद को जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। इसी तरह बाबा मोहनदास एग्रो शॉप में स्टॉक, पीओएस एंट्री और भौतिक भंडारण में विसंगति पाई गई। इसे उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 का उल्लंघन मानते हुए दुकान पर 21 दिनों का विक्रय प्रतिबंध लगाया गया है।

कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने पुलिस उपायुक्त मयंक ने नार्थ जोन के अधिकारियों की ली बैठक

विजिबल पुलिसिंग, रात्रि गश्त और नशे पर सख्ती के दिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

पुलिस उपायुक्त कार्यालय नार्थ जोन में आज पुलिस उपायुक्त मयंक गुर्जर ने जोन के राजपत्रित अधिकारियों तथा उरला और पंडरी अनुभाग के थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कानून-व्यवस्था मजबूत करने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए गए।

विजिबल पुलिसिंग पर जोर

पुलिस उपायुक्त ने आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विजिबल पुलिसिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। बैंकों और एटीएम की नियमित चेकिंग, रात्रि गश्त को सघन और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। रात्रि गश्त में बल बढ़ाने और नई गश्त प्रणाली तैयार करने पर भी चर्चा हुई।

गुंडा-बदमाशों पर निगरानी और नशे पर कड़ी कार्रवाई

असामाजिक तत्वों, गुंडा-बदमाशों और आदतन अपराधियों पर सतत निगरानी रखने तथा थाना हाजिरी कराने के निर्देश दिए गए। चाकूबाजी, नशे से जुड़े अपराधों और अन्य अवैध गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई के आदेश दिए। शराब भट्ठियों, अहातों, होटल, लॉज, ढाबा और सार्वजनिक स्थलों पर नियमित चेकिंग अभियान चलाने को कहा गया।

महिला-बाल अपराध और साइबर क्राइम पर फोकस

बैठक में बाल अपराध, महिला अपराध, भारतीय न्याय संहिता के तहत गंभीर अपराधों और साइबर अपराधों में तुरंत संज्ञान लेकर शीघ्र कार्रवाई पर जोर दिया गया। बस्तियों और संवेदनशील क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों और अड्डेबाजों की चेकिंग, संदिग्ध वाहनों की जांच के निर्देश दिए गए।

अनुशासित पुलिसिंग के निर्देश

आम नागरिकों से शालीन और सहयोगात्मक व्यवहार बनाए रखने तथा पुलिस कर्मचारियों में अनुशासन रखने को कहा गया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नार्थ जोन आकाश मरकाम, एसीपी उरला पूणिर्मा लामा सहित नार्थ जोन के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी मौजूद रहे।

रायपुर की 'लेडी डॉन' मुस्कान रात्रे 6 जिलों से जिला बदर

रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने मादक पदार्थों की बिक्री करने वाली कुख्यात आदतन बदमाश मुस्कान रात्रे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे 3 माह के लिए जिला बदर कर दिया है। रायपुर में 'लेडी डॉन' के नाम से कुख्यात मुस्कान अब रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगी। **नशे के कारोबार से मारपीट तक, 20 से अधिक केस दर्ज :** डीसीपी सेंट्रल जोन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार मुस्कान रात्रे लंबे समय से नशीले पदार्थों और अवैध शराब के कारोबार में सक्रिय थी। उसके खिलाफ मारपीट, धमकी, हत्या का प्रयास, अवैध गांजा बिक्री समेत कुल 20 से अधिक संगीन अपराध विभिन्न थानों में दर्ज हैं। लगातार प्रतिबंधात्मक और दंडात्मक कार्रवाई के बाद भी उसके आपराधिक आचरण में कोई सुधार नहीं आया। **छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई :** पुलिस कमिश्नर रायपुर ने मध्य जिला पुलिस के प्रतिवेदन, आपराधिक इतिहास, स्वतंत्र साक्षियों के कथन और अभिलेखों के परीक्षण के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत जिला बदर का आदेश जारी किया। आदेश 3 माह तक प्रभावी रहेगा। **आदेश उल्लंघन पर होगी अलग कार्रवाई :** जिला बदर अवधि में मुस्कान रात्रे बिना सक्षम अनुमति के इन 6 जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगी। उल्लंघन करने पर पृथक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से अपराधी के प्रभाव क्षेत्र को समाप्त कर अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण लगेगा। साथ ही नागरिकों, व्यापारियों और गवाहों में व्याप्त भय दूर होगा। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि अपराध और अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। मुस्कान रात्रे की गिरफ्तारी और जिला बदर की कार्रवाई को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

आईसीएआर-एनआईबीएसएम ने "खेत बचाओ अभियान" के तहत किसानों को दिया गया प्रशिक्षण

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

आईसीए आरङ्ग राष्ट्रीय जैविक स्ट्रैस प्रबंधन संस्थान, रायपुर द्वारा संचालित "खेत बचाओ अभियान" के अंतर्गत सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने एवं मृदा स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से एक व्यापक किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बेलटुकरी, कुररा, नौगांव एवं पवनी ग्रामों के 51 किसान एवं महिला किसानों ने सक्रिय सहभागिता की।

कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के निदेशक डॉ. पीके राय के संबोधन से हुआ। उन्होंने किसानों को खेत बचाओ अभियान के उद्देश्यों एवं महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध एवं असंतुलित उपयोग के कारण मृदा की उर्वरता एवं उसके समग्र स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मृदा की गुणवत्ता को पुनर्स्थापित करना तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर कृषि भूमि की उत्पादक क्षमता को सुदृढ़ बनाना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को संस्थान के प्रायोगिक प्रक्षेत्र का भ्रमण भी कराया गया, जहाँ कार्यक्रम समन्वयक एवं संयुक्त निदेशक डॉ. पंकज शर्मा ने मूंग की फसल का हरी खाद के रूप में उपयोग करने का सजीव प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि हरी खाद के प्रयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, मृदा की संरचना में सुधार होता है तथा दीघर्कालिक रूप से मृदा स्वास्थ्य एवं कृषि की स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

तकनीकी सत्रों के दौरान संयुक्त निदेशक डॉ. अनिल दीक्षित ने विभिन्न प्रकार की हरी खाद वाली फसलों एवं मृदा उर्वरता बनाए रखने में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इसके माध्यम से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम किया जा सकता है तथा मृदा स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

किसानों को संबोधित करते हुए संयुक्त निदेशक डॉ. कल्याण मंडल ने जैव उर्वरकों एवं जैव नियंत्रक एजेंटों के उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने किसानों से पर्यावरण हितैषी कृषि तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया, जिससे टिकाऊ फसल उत्पादन एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

छत्तीसगढ़ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की हुई 27वीं क्षेत्रीय बैठक

श्रम सचिव ने मृत्यु क्लेम और निष्क्रिय खातों पर तेज कार्रवाई करने के निर्देश दिए

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय 27वीं बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता ने की। श्री गुप्ता ने निर्देश दिए है कि मृत्यु प्रकरणों में तेजी से ईएसआईसी के साथ समन्वय कर उद्योगों में होने वाले आकस्मिक मृत्यु प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर तत्काल निपटाया जाए। सचिव ने कहा कि निष्क्रिय भविष्य निधि खातों के लाभार्थियों की पहचान कर उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में प्रत्येक माह की 27 तारीख को आयोजित निधि आपके निकट कार्यक्रम में जिला कलेक्टर, ईएसआईसी सहायक श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त एवं संबंधित राज्य सरकार के विभागों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए।

बैठक का संचालन सदस्य सचिव एवं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त जयवदन इंगले द्वारा किया गया। क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त जयवदन इंगले ने बैठक में संगठन की व्याप्ति, न्यायालयीन प्रकरणों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, कमर्चारी पंजीकरण योजना 2025, प्रयास, तत्पर, कन्वर्जेंस बैठक तथा नवीन साइट्स प्रोजेक्ट की प्रगति पर जानकारी दी। उन्होंने सभी सदस्यों से अपील की कि वे नियोक्ताओं एवं पीएफ सदस्यों को निधि आपके निकट कार्यक्रम में भाग लेकर समस्याओं का समाधान कराने हेतु प्रोत्साहित करें। उल्लेखनीय है कि कमर्चारी भविष्य निधि क्षेत्रीय समिति प्रत्येक राज्य में सांविधिक प्रावधानों के तहत गठित एक महत्वपूर्ण परामशर्दात्री समिति है। बैठक में छत्तीसगढ़ में ईपीएफ अधिनियम के अनुपालन, सामाजिक सुरक्षा लाभों के विस्तार तथा कार्यालय की उपलब्धियों एवं चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में उप केंद्रीय श्रमायुक्त बिधान चंद्र नायक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उप निदेशक एन.के. पटनायक एवं रत्नेश राजन्या उपस्थित रहे। नियोक्ता पक्ष से छग उद्योग महासंघ के अध्यक्ष महेश कक्कड़ और उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग सम्मिलित हुए। कर्मचारी प्रतिनिधि के रूप में राधेश्याम जायसवाल, ईश्वर चंदेल, शंख ध्वनि सिंह एवं एचएस मिश्रा ने भाग लिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर की ओर से क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-जयवदन इंगले, क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त गौरव डोगरा एवं देबाशीष चांद तथा सहायक भ.नि. आयुक्त आकाश अग्रवाल उपस्थित थे। पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति गौरव डोगरा ने दी।

बस्तर में दूध, खेतों तक पानी, युवाओं को काम और गांवों को नई पहचान देने हो रही तैयारी

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री साय ने रखा विकसित छग का विजन, आमदनी दोगुनी करने बड़ा संकल्प : हर परिवार की आय 30 हजार रुपये प्रतिमाह तक पहुंचाने का लक्ष्य

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में नक्सलवाद से मुक्त बस्तर की नई तस्वीर देश के सामने रखी। उन्होंने कहा कि दशकों तक हिंसा की मार झेलने वाला बस्तर अब आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और कृषि आधारित विकास का मॉडल बनेगा।

मुख्यमंत्री ने बैठक में बस्तर के आदिवासी परिवारों की आय दोगुनी करने, दुग्ध क्रांति लाने, 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने, पर्यटन को बड़े उद्योग के रूप में विकसित करने तथा एआई और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की व्यापक कायर्योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर अब नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। वहां दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, खेतों तक पानी पहुंचाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, गांवों में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले तीन वर्षों में बस्तर के परिवारों की मासिक आय बढ़ाकर 30 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वतर्मान में बस्तर के लगभग 85 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है। सरकार खेती, पशुपालन, वन उपज, छोटे उद्योग और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में डेयरी मॉडल को तेजी से लागू किया जा रहा है। इसके तहत आदिवासी परिवारों को दुधारू गाय और भैंस उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य गांवों में स्थायी आय का स्रोत तैयार करना है। इस पहल से महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा गांवों में डेयरी केंद्र, दूध संग्रहण, परिवहन और स्थानीय बाजार जैसी नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं से 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इंद्रावती नदी क्षेत्र में सालभर पानी उपलब्ध होने से खेती बेहतर होगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसान धान के साथ-साथ सब्जियां, फल तथा अन्य नकदी फसलें भी उगा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगभग 36 लाख लोगों की डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार की जा रही है। इससे मरीजों के इलाज, बीमारी और दवाओं का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा तथा डॉक्टरों को समय पर सही जानकारी मिल सकेगी। इसका सबसे अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं और बुजुर्गों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि बस्तर में बने लगभग 200 सुरक्षा शिविरों को अब सेवा डेरा के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को राशन, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, बैंकिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की 371 योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चित्रकोट और बौद्ध धर्म से जुड़े तीर्थस्थल सिरपुर को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। बस्तर में वॉटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और जंगल सफारी जैसी गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है, जबकि सिरपुर में ग्लोबल मेडिटेशन सेंटर, संग्रहालय और महानदी तट के विकास पर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकता है। पर्यटकों के आने से होटल, परिवहन, गाइड, हस्तशिल्प, दुकानदारों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मिलता है। बस्तर को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने से हजारों युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार निवेश, सुशासन और तकनीक आधारित विकास को तेजी से आगे बढ़ा रही है। राज्य में 435 सुधार लागू किए गए हैं और सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत बनाकर निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की दो आधुनिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और डिजिटल तकनीक के जरिए विकास का नया मॉडल तैयार किया जा रहा है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में 100 करोड़ रुपये की लागत से एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है। इसके साथ ही 341 पीएमश्री स्कूल, 5,857 स्मार्ट क्लासरूम और 16 स्थानीय भाषाओं में द्विभाषी पुस्तकों के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

संपादकीय

नरेंद्र मोदी सबसे भरोसेमंद व ईमानदार नेता हैं

देश की राजनीति में लोकप्रिय,महान नेता व बड़े नेता तो बहुत हुए हैं और आगे भी बहुत होंगे लेकिन नरेंद्र मोदी देश ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय, भरोसेमंद व ईमानदार नेता हैं,इस बात से देश के भीतर भारतीयों को जितना गर्व होता है, उससे ज्यादा गर्व विदेश में रहने वालों भारतीयों को होता है ।उनमें जो एक ईमानदारी का गुण हैं, वह उन्हें देश ही नहीं विदेश के नेताओं के बीच भी अलग पहचान देता है। वह सबसे अलग इसलिए लगते हैं, माने जाते हैं कि वह पूरे ईमानदार हैं। पूरे ईमानदार होने के कारण उन पर लोग पूरा भरोसा करते हैं। उन पर लोग पूरा भरोसा करते हैं, इसलिए वह सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। बाकी नेता अपने दूसरे गुणों के कारण लोकप्रिय होते हैं लेकिन पीएम मोदी ईमानदारी के कारण सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, बाकी नेताओं की ईमानदारी पर संदेह किया जा सकता है लेकिन पीएम मोदी की ईमानदारी पर जरा भी संदेह नहीं किया जा सकता ।पीएम मोदी के आचार विचार को बरसों देखने वालों को भी हैरत होती है कि कोई आदमी इतना ईमानदार कैसे हो सकता है।

देश की जनता ने देखा है कि पांच साल के लिए कोई नेता मंत्री, सीएम, विधायक, सांसद बन जाता है तो पांच साल सत्ता में रहने के कारण वह भ्रष्ट हो जाता है। उसकी संपत्ति बढ़ जाती है, उसके परिवार के लोगों की संपत्ति बढ़ जाती है, पांच साल में ही धन कमाना सबसे प्रमुख काम हो जाता है। जितने साल नेता सत्ता में रहता है उतना धन का मोह बढ़ जाता है। कई नेताओं का धन का लोभ निरंतर सत्ता में रहने के कारण बढ़ता जाता है ऐसे में पीएम मोदी को देश की जनता देखती है तो उसे लगता है देश के नेताओं को पीएम मोदी के समान ईमानदार होना चाहिए।

पीएम मोदी 13 साल गुजरात के सीएम रहे तब भी उनको धन का मोह नहीं था,सीएम रहते लोग कई पीढ़ियों के लिए धन कमा लेते हैं लेकिन पीएम मोदी ने सीएम रहते, पीएम रहते न तो अपने लिए गलत तरीके से धन कमाया और न ही उनके परिवार के लोगों को उनके सीएम, पीएम रहने का कोई फायदा उठाने दिया। वह पं. नेहरू से ज्यादा दिनों तक पीएम पद पर रहे हैं यह एक रिकार्ड बना है लेकिन लोग उनको इस रिकार्ड के लिए जितना याद करेंगे उससे ज्यादा इस बात के लिए याद करेंगे कि वह सीएम रहते जितने ईमानदार थे, पीएम रहते भी उतने ईमानदार रहे। 25 साल सत्ता में रहने के बाद उनके दामन में बेईमानी का एक दाग नहीं है। जैसे महात्मा गांधी के विषय में कहा जाता है कि सौ दो सौ साल लोगों को यकीन नहीं होगा कि इस धरा पर कोई महात्मा गांधी जैसा नेता हुआ था, उसी तरह सौ साल बाद लोगों को यकीन नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार नेता भारत में हुआ था।

पीएम मोदी ने सत्ता को स्वयंसेवा या परिवार सेवा या पार्टी सेवा का माध्यम नहीं माना, उसे विशुध्द रूप से जनसेवा का माध्यम माना यही वजह है कि सीएम रहते उन्होंने एक प्रदेश में जनसेवा की तो पीएम बनने पर वह 12 सालों से देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। देश की जनता पीएम मोदी पर भरोसा करती है कि यह आदमी सत्ता का दुरुपयोग दूसरे नेताओं की तरह नहीं करेगा, यही वजह है कि जनता उन पर भरोसा करती है और उनको देश के चुनाव में लगातार जिताती आ रही है और पीएम मोदी भी जनता के भरोसे की कसौटी पर अब तक खरे उतरे हैं। उन्होंने जनता से जो वादा किया वह पूरा किया ।जनता के लिए,देश के लिए जो जरूरी लगा वह पहले किया। देश प्रथम वह कहते ही नहीं है, वह देश प्रथम के लिए वह सब करते हैं जो करना जरूरी होता है।

देश आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए तो देश को उन्होंने आर्थिक रूप से मजबूत किया है। देश सैन्य रूप से मजबूत होना चाहिए तो देश की सेना की मजबूती के लिए वह सब किया है जिससे आज देश की सेना विश्व की मजबूत सेनाओं मे से एक मानी जाती है ।देश के विकास के लिए वह जितने संवेदनशील रहे है,देश की विरासत के लिए उतने ही संवेदनशील रहे हैं ।देश के कई तीर्थस्थलों को जो भव्य रूप मिला है, वह पीएम मोदी की विकास के साथ विरासत का पूरा ख्याल रखने के कारण ही मिला है। वह देश के पहले ऐसे पीएम हैं जिन्होंने देश के विकास के साथ ही विरासत का भी पूरा ख्याल रखा है और जो जरूरी समझा उसे बेझिझक किया है ।तीर्थस्थलों के विकास से किसी क्षेत्र का विकास कितना हो सकता है, इसे उन्होंने अयोध्या,काशी,उज्जैन में करके दिखाया है ।देश को बताया कि देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बड़े बड़े उद्योगों के साथ ही बडे भव्य तीर्थस्थल भी जरूरी होते हैं।

दूसरे नेताओं व पीएम मोदी में एक अंतर यह भी देखा जा सकता है कि पीएम मोदी जो जिस काम का भूमिपूजन करते हैं, वही उस काम का शुभारंभ भी करते हैं, दूसरे नेताओं की तरह वह सिर्फ शिलान्यास नहीं करते हैं, उसे पूरा भी कराते है और वह जो काम करने की सोचते हैं, वह भव्य होता है और सबसे बड़ा होता है। भारत मंडपम,नया संसद भवन,कर्तव्य पथ, पीएम सचिवालय, बड़े पुल, बड़े टनल, सबसे ऊंचा पुल, सबसे लंबा पुल,सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ी मूर्ति,अयोध्या में सबसे भव्य मंदिर आदि इस बात के उदाहरण है कि पीएम मोदी ने कुछ काम ऐसे किए हैं कि उनको उस काम के लिए सदियों याद किया जाता रहेगा।

सहूलियत, सम्मान और सेहत... हर घर नल से बदली जिंदगी

कमलेश साहू, सहायक संचालक जनसंपर्क, रायपुर

रोज सुबह उठते ही घर में नल से साफ पानी आते देखने की खुशी क्या होती है, इसे कमली से पूछिए। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव को अपने आंगन में लगे नल से आ रहे पानी की धार को दिखाते खुशी से उनकी आंखें डबडबा गई। जल जीवन मिशन ने कमली जैसी हजारों महिलाओं को अमूल्य खुशियां दी हैं। कभी पीने और निस्तारी के पानी के लिए दिनभर चिंतित रहने वाली इन महिलाओं का जीवन घर में लगे नल ने बदल दिया है।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव अपने चार दिनों के बस्तर प्रवास के दौरान जल जीवन मिशन का काम देखने कमली के भी गांव पहुंचे। कमली के गांव बस्तर जिले के तोकापाल विकासखण्ड के दुगनपाल में उन्होंने कुछ और घरों में भी जाकर नल से पानी आते देखा। जल जीवन मिशन से घर में पानी पहुंचने की खुशी सभी महिलाओं के चेहरे पर दिख रही थी।

जल जीवन मिशन दूरस्थ गांवों और वनांचलों की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है। आधी आबादी के एक बड़े हिस्से को पीने के पानी के लिए रोज जूझना पड़ता था। खासतौर से गमियों के दिनों में जब हर साल सिर पर पानी के बर्तन का सफर कुछ सौ मीटरों से कुछ किलोमीटरों में बदल जाता था।

जीवन के लिए अनिवार्य जरुरत पानी की व्यवस्था गमियों में महिलाओं का जीवन दुष्कर बना देती थी। दुगनपाल में भी महिलाओं को रोज गांव के हैंडपंप या कुआं पर जाकर घर के सभी लोगों के लिए पानी का इंतजाम करना पड़ता था। घर में नल लग जाने से अब इस समस्या से निजात मिल गई है। जल जीवन मिशन के काम जैसे-जैसे पूरे होते जा रहे हैं, महिलाओं की बाहर से पानी लाने की चिंता और तकलीफ दूर होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक साढ़े आठ हजार से अधिक योजनाओं को पूर्ण कर संचालन के लिए पंचायतों को सौंपा जा चुका है।

जल जीवन मिशन महज हर घर तक पेयजल पहुंचाने की योजना नहीं है। यह महिलाओं की दिनचर्या और जीवन में भी बड़ा बदलाव ला रहा है। गांवों में परंपरागत रूप से घर में पेयजल और अन्य जरूरतों के लिए पानी के इंतजाम का जिम्मा महिलाओं पर ही है। घर तक पानी की पहुंच न होने के कारण उन्हें हैंडपंपो, सार्वजनिक नलों, कुंओं या अन्य स्रोतों से रोज पूरे परिवार के लिए जल संग्रहण करना पड़ता है।

रोजाना का यह श्रमसाध्य और समयसाध्य काम बारिश तथा भीषण गर्मी के दिनों में और कठिन हो जाता है। कई इलाकों में गमियों में जलस्रोतों के सूख जाने के कारण दूर-दूर से पानी लाने की मजबूरी रहती है। परिवार के लिए पानी की व्यवस्था हर दिन का संघर्ष बन जाता है। महिलाओं के दिन के कई घंटे इसी काम में निकल जाते हैं।

जल जीवन मिशन हर घर तक नल से जल पहुंचाने के साथ ही महिलाओं को कई समस्याओं से निजात दिला रहा है। घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचने से वे कई चिंताओं से मुक्त हो गई हैं। अब रोज-रोज पानी के लिए बहुत सारा श्रम और समय नहीं लगाना पड़ता। इससे उन्हें घर के दूसरे कामों, बच्चों की परवरिश, खेती-बाड़ी एवं आजीविका के अन्य कार्यों के लिए अधिक समय मिल रहा है और वे इन कार्यों पर अपना ज्यादा ध्यान व समय दे पा रही हैं।

जल जीवन मिशन से बारहों महीने घर पर ही जलापूर्ति से लगातार बारिश तथा गर्मी के दिनों में बाहर से पानी लाने की मुसीबत दूर हो गई है। गमियों में जलस्तर के नीचे चले जाने से तथा बरसात में लगातार बारिश से जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। गुणवत्ताहीन पेयजल से पेट तथा निस्तारी के लिए खराब जल के उपयोग से त्वचा संबंधी रोगों का खतरा रहता है। जल जीवन मिशन ने सेहत के इन खतरों को भी दूर कर दिया है।

गुल्लक से क्रेडिट कार्ड तक : बचत के विरोधाभासी चक्र में फंसी पीढ़ी

केवल तिवारी

बचत करने की आदत हम भारतीयों के स्वभाव के मूल में है। देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग तरीके की गुल्लक संस्कृति है। कभी बच्चों के शादी-ब्याह के नाम पर आय का एक हिस्सा बचाकर रखना तो कभी घर बनाने के लिए बचत। छोटी-छोटी बचत अनेक बार बड़ी काम आती है। बचाने की इस प्रवृत्ति के कारण ही अनेक बार मंदी के दौर में उतना बड़ा झटका आम लोगों को नहीं लगा, जितनी आशंका जताई गयी थी। नोटबंदी के दौरान गुल्लक संस्कृति काम आई। बड़े नोट बंद हुए, लेकिन छोटी-छोटी बचत वालों ने उस दौर में अपने इन छोटे नोटों से ही काम चलाया। इस बचत की संस्कृति को समझते हुए अनेक सरकारों ने भी समय-समय पर कई योजनाएं शुरू कीं। मसलन—किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडो लक्ष्मी, कन्या सुमंगल, महिला सम्मान बचत वगैरह-वगैरह।

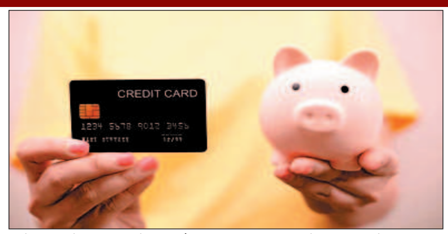

लेकिन आज, बदले वैश्विक परिदृश्य में सत्ता के शिखर से बचत का एक अन्य मंत्र दिया जा रहा है। विदेश यात्राओं से परहेज करें। अभी आभूषण नहीं खरीदें। ईंधन बचाएं। अघोषित तरीके से सीधा संदेश यह भी है कि बचत करें। आज की युवा पीढ़ी विरोधाभास के चक्रव्यूह में फंसी है। वह घूमने-फिरने की शौकीन है। वह नये-नये कपड़े खरीदने, खानपान के नये अड्डों में जाने और आभूषणों को खरीदने की शौकीन है। यह पीढ़ी क्रेडिट कार्ड संस्कृति वाली है। जितना है, उससे भी ज्यादा खर्च करने में विश्वास। यानी इस पीढ़ी को बचत की बहुत ज्यादा फिक्र नहीं है। पहले से ही खुलकर खर्च करने वाली इस पीढ़ी को लेकर रही-सही कसर आयकर प्रणाली की नयी व्यवस्था ने पूरी कर दी है। करीब 12 लाख रुपये तक कोई कर नहीं, उसके बाद बचत का कोई फायदा नहीं। पुरानी व्यवस्था में टैक्स बचाने के नाम पर ही सही, नौकरी-पेशा व्यक्ति एक सीमा तक बचत करने की कोशिश करता था। शायद इसी बहाने कुछ बच जाये। अब, चूंकि बचत योजनाओं से ज्यादा फायदा होना ही नहीं है तो उस ओर सोचना ही क्या?

प्रोविडेंट फंड योजना में अभी बेसिक वेतन का 12 प्रतिशत जमा होने का प्रावधान है। इसे 30 प्रतिशत तक बढ़ा भी सकते हैं। आमतौर पर इसे सेवानिवृत्ति के लिए बचाया गया धन माना जाता है। इस बचत से पैसा निकालना कठिन होता था। अभी तक भी ऐसा ही है, लेकिन अब इसमें भी नयी व्यवस्था पर काम लगभग पूरा हो चुका है। इस बचत को भी अब सेविंग अकाउंट की तरह बनाने की कवायद चल रही है। यानी एटीएम की तरह इसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं। नयी व्यवस्था के मुताबिक कमर्चारी को अपने नियोक्ता से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। गौर हो कि पहले पीएफ राशि निकालना बहुत आसान नहीं था। अब नयी व्यवस्था में अपने कुल पीएफ राशि का पचास से 75 फीसदी तक सीधे निकाला जा सकता है। हालांकि, बदले नियमों के तहत खाते में हर समय कुल योगदान का न्यूनतम 25 प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित रखना अनिवार्य है।

एक तरफ बचत की बात और दूसरी ओर खर्च करने के लिए इतनी छूट। आज का युवा वर्ग बचत के इस मंत्र में विरोधाभास के चक्रव्यूह में फंस गया है। चक्रव्यूह का पहला द्वार तो वे खुद ही हैं। खाओ-पीओ, घूमो-फिरो और ऐश करो की नीति। इस द्वार को किसी तरह पार कर भी लें या यूं कहें कि अपनी आदतों पर किसी तरह काबू पा भी लें तो दूसरा द्वार आयकर में अब बचत प्रावधान करीब-करीब खत्म। टैक्स स्लैब में फायदा मिलना ही नहीं है या टैक्स कटना ही है तो कोई अतिरिक्त बचत करके फायदा क्या? इसे भी पार पाने की जुगत कर ले। या बचत जरूरी है मानकर कुछ बचा भी ले तो अब पीएफ से निकासी की नयी व्यवस्था।

यह तो सवर्मान्य सत्य है कि घर-गृहस्थी में रुपयों की जरूरत आये दिन रहती है। अपनी कमाई से भी अधिक की जरूरत होती है। इस पर साधारण-सा मनोवज्ञान है कि लोन आदि लेने से पहले व्यक्ति अपनी ही बचत पर नजर डालता है। ऐसे में उसे अब सबसे पहले पीएफ ही नजर आएगा। वैसे जानकार कहते हैं कि बेशक आज का युवा इससे पहले की पीढ़ी के लोगों से जरा हटकर है, लेकिन वह शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और एसआईपी (सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) में दूसरी तरह से बचत करता है। हालांकि ये सब “सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क” हैं, लेकिन वह जोखिम ले लेता है। इसमें कुछ पार पा लेते हैं, कुछ गंवा बैठते हैं। “जनरेशन गैप” के तथ्यों से इतर वह भविष्य की योजनाएं भी करता है, उसका स्वरूप दूसरा होता है। उसके फोन में बचत विशेष के कई एप हैं।

बदलते दौर में यह तो मानकर चलना पड़ेगा कि बेशक बचत मंत्र में विरोधाभास हो, लेकिन नयी पीढ़ी विरोधाभास के चक्रव्यूह से निकल ही जाएगी। फिर नियम भी बदलते रहते हैं, समय चक्र की तरह। विरोधाभास के इस चक्रव्यूह को तोड़ने की जरूरत पड़ी तो वह बाहर आने की कोशिश कर लेगा। हां, ध्यान रखना होगा कि कहीं बाहर निकलने की तेज आपाधापी में वह अंतिम पायदान पर कहीं घिर न जाये। क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनियों की चकाचौंध में “हायर एंड फायर” का ऐसा प्रावधान भी छिपा है जो पलभर में अर्श से फर्श पर ले आता है।

भारत ने श्रमिकों, किसानों, एमएसएमई के लिए खाड़ी देश में अवसरों के द्वार खोल

पीयूष गोयल

एक जून से लागू हुआ भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस मिशन की एक निर्णायक उपलब्धि है, जिसका लक्ष्य नए बाजार खोलने और रोजगार सृजन को गति देने के जरिये भारत के छात्रों, कारीगरों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई के लिए वैश्विक समृद्धि के मार्ग बनाना है। भारत और ओमान के बीच गहरे आर्थिक संबंध हैं और लोगों के आपसी संबंध प्रगाढ़ हैं। ओमान में लगभग 7 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें वे व्यापारी परिवार भी शामिल हैं, जिनकी जड़ें 200-300 साल पुरानी हैं। ओमान से भारत को भेजी जाने वाली वार्षिक धनराशि लगभग 2 बिलियन डॉलर है, जबकि देश में 6,000 से अधिक भारतीय उद्यम कार्यरत हैं।

दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ करता है। यह तुरंत ही ओमान में 98% टैरिफ लाइनों के लिए 100 प्रतिशत शुल्क मुक्त बाजार पहुंच की सुविधा देता है, जिसमें 99.38 प्रतिशत निर्यात शामिल है। यह सीईपीए से पहले की प्रणाली की तुलना में एक उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है। पहले की प्रणाली में केवल 15.3 प्रतिशत भारतीय निर्यात ओमान में शून्य शुल्क के साथ प्रवेश कर सकते थे। भारत की ऐसी वस्तुएं, जिन पर वतर्मान में ओमान में 5 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है और जिनकी कीमत लगभग 3.64 बिलियन डॉलर के निर्यात के बराबर है, अब काफी अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी।

भारत के एमएसएमई क्षेत्र के लिए, यह समझौता परिवर्तनकारी हो सकता है, क्योंकि सीईपीए से लाभान्वित होने वाले कई क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों की प्रमुखता है। लोहा और इस्पात, वस्त्र, चमड़ा, वाहन कल-पुर्जे और औद्योगिक उपकरण जैसे कुछ क्षेत्रों में एमएसएमई को बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जिससे उत्पादन, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ती वैश्विक अस्थिरता के युग में, सीईपीए भारतीय निर्यातकों को, जो आर्थिक मंदी और बढ़ते व्यापार बाधाओं का सामना कर रहे हैं, अपने बाजारों को विविध बनाने और परंपरागत बाजारों पर निर्भरता कम करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। रोजग़ार सृजन — यह व्यापार समझौता श्रम-गहन क्षेत्रों जैसे वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण और कुछ इंजीनियरिंग क्षेत्रों को लाभ पहुँचाता है, जो भारत के प्रमुख रोजगार प्रदाता हैं।

ओमान को होने वाले वस्त्र निर्यात में वृद्धि से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और तिरुपुर, सूरत, लुधियाना, पानीपत, कोयंबटूर, करूर, भदोही, मुरादाबाद, जयपुर और अहमदाबाद जैसे प्रमुख क्लस्टर में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। भारत भर के कारीगर और बुनकर भी अपने उत्पादों की उच्च अंतरराष्ट्रीय मांग से लाभान्वित होंगे। भारत भर में, विशेष रूप से तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, साथ ही महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों समेत चमड़ा और जूता के प्रमुख केंद्रों में भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

रत्न और आभूषण क्षेत्र एक अन्य उदाहरण है, जो दिखाता है कि सीईपीए रोजगार वृद्धि को किस प्रकार तेज करेगा। भारत के पास पहले से ही कटे और पॉलिश किए हुए हीरे, सोने और चांदी के आभूषण तथा हस्तनिर्मित आभूषण उत्पादन में मजबूत क्षमताएं हैं। शुल्क बाधाओं के हटने से, भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय और एशियाई प्रतिस्पर्धियों पर निर्णायक बढ़त मिलेगी। उद्योग जगत का अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में ओमान को होने वाला निर्यात बढ़ कर 150 मिलियन डॉलर तक हो सकता है। इससे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के आभूषण निर्माण केन्द्रों में महत्वपूर्ण रोजगार संभावनाएं सृजित होने की उम्मीद है।

किसान और मछुआरे - घरेलू किसानों और संवेदनशील कृषि हितों की सुरक्षा के लिए, भारत ने गेहूं, चावल, मक्का, मोटे अनाज, डेयरी, फल, सब्जियां, खाद्य तेल, तिलहन, चाय, कॉफी और शहद जैसे प्रमुख उत्पादों पर कोई टैरीफ छूट नहीं दी है। घी, शहद, मीठे बिस्कुट, अंडे और कुछ मिष्ठान्न उत्पादों में भारत को प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा, जिससे देश के कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी और ग्रामीण आय में वृद्धि होगी। यह समझौता भारत के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) प्रमाणन की स्वीकृति और मान्यता भी प्रदान करता है, जो भारतीय किसानों को ओमान में, जो एक प्रमुख खाद्य आयातक है, जैविक उत्पाद बेचने के लिए विशाल अवसर देगा।

समुद्री उत्पादों में भी विशाल संभावनाएँ हैं, जिनका अब तक उपयोग नहीं हो पाया है। 2022 और 2024 के बीच ओमान का समुद्री उत्पादों का आयात लगभग 119 मिलियन डॉलर था। भारत से आयात केवल 7.75 मिलियन डॉलर था, जिससे भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात जैसे झींगा और जमे हुए कटलफिश के लिए विशाल अवसर मौजूद हैं। श्रम-गहन समुद्री उत्पाद उद्योग मछली पकड़ने, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, शीत-श्रृंखला लॉजिस्टिक्स और निर्यात संचालन में अतिरिक्त नौकरियाँ उत्पन्न कर सकता है। दवा और पारंपरिक चिकित्सा - यूएसएफडीए, ईएमए, यूके एमएचआरए और टीजीए जैसे नियामकों द्वारा अनुमोदित भारतीय दवाएं 90 दिनों के भीतर ओमान में स्वचालित विपणन प्राधिकार प्राप्त करेंगी — जो भारतीय फार्मा निर्यातकों के लिए एक बड़ी सफलता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सीईपीए भारत की पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं के लिए अवसर पैदा करता है। यह पारंपरिक चिकित्सा में संयुक्त अनुसंधान की व्यवस्था करता है।

सेवाएँ और आवागमन - समझौते का एक और महत्वपूर्ण पहलू सेवा और आवागमन में निहित है। ओमान ने भारत के लिए विशिष्ट निर्यात क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की है, जिनमें पेशेवर सेवाएँ, कंप्यूटर और आईटी सेवाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, अनुसंधान और विकास तथा पर्यावरण सेवाएँ शामिल हैं। लेखा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, निर्माण, शिक्षा और परामर्श जैसे क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों को बेहतर बाजार पहुँच से लाभ मिलने की उम्मीद है। महत्त्वपूर्ण रूप से, ओमान ने भारतीय पेशेवरों और श्रमिकों के लिए आवागमन प्रतिबद्धताओं में वृद्धि पर सहमति व्यक्त की है। अंतर-कॉर्पोरेट स्थानांतरित कर्मियों और संविदा सेवा प्रदाताओं को चार साल तक रहने की अनुमति दी जाएगी, जबकि व्यवसाय आगंतुकों और स्वतंत्र पेशेवरों को आसान अस्थायी प्रवेश की सुविधा मिलेगी। इसने अंतर-कॉर्पोरेट स्थानांतरित कर्मियों के लिए ऊपरी-सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।

विकसित देशों के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की मोदी सरकार की पहल प्रत्येक भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने के प्रधानमंत्री के मिशन का हिस्सा है। ओमान के साथ समझौता याद दिलाता है कि व्यापार; विकास, रोजगार सृजन और साझा समृद्धि का एक शक्तिशाली उपकरण है। एक विभाजित और संरक्षणवादी दुनिया में, पीएम मोदी स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि एक नया, आत्मविश्वासी भारत पीछे नहीं हटेगा। यह साझेदारियों, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक सहभागिता के माध्यम से आगे बढ़ेगा।

(लेखक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं।)

फुलाया गया गुब्बारा फूट चुका

फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने से सिर्फ दस दिन पहले फीफा को सस्ते में प्रसारण अधिकार बेचने पड़े हैं। यह घटनाक्रम बताता है कि भारतीय बाजार को लेकर फुलाया गया गुब्बारा अब फूट चुका है।

जी ग्रुप का फिर से खेल प्रसारण के क्षेत्र में उतरना अच्छी खबर है। रिलायंस ग्रुप के डिज्नी हॉटस्टार को खरीद लेने और सोनी लिव के भारतीय बाजार में हाथ खींच लेने के बाद जियो-हॉटस्टार की लगभग मोनोपॉली बन गई थी। अब जी ग्रुप ने 11 जून से शुरू हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप का टीवी एवं डिजिटल प्रसारण अधिकार खरीद कर फिर से प्रतिस्पर्धा की संभावना जगाई है। बहरहाल, इस क्रम में भारतीय खेल प्रसारण बाजार के सिकुड़ने के संकेत भी मिले हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के प्रसारण का अधिकार रिलायंस ग्रुप के वायकॉम-18 एवं जियो सिनेमा ने तकरीबन छह करोड़ डॉलर में खरीदे थे।

अब चार साल जी ने 2026 और 2030 के वर्ल्ड कप समेत फीफा के नौ टूर्नामेंट्स के प्रसारण का अधिकार सिर्फ साढ़े तीन करोड़ डॉलर में खरीद लिए हैं। बताया जाता है कि 2022 में वर्ल्ड कप प्रसारण के दौरान सिर्फ करीब 300 करोड़ रुपये के विज्ञापन ही जुटाए जा सके। इस कारण इस बार इस टूर्नामेंट का बाजार भाव गिर गया। फीफा ने आरंभिक कीमत सिर्फ 2026 के टूर्नामेंट के लिए 10 करोड़ डॉलर रखी थी। जियो हॉटस्टार ढाई करोड़ डॉलर से ज्यादा देने को तैयार नहीं हुआ। सोनी भी शुरुआती बातचीत के बाद मैदान से हट गया। तो टूर्नामेंट शुरू होने से सिर्फ दस दिन पहले फीफा को सस्ते में प्रसारण अधिकार बेचने पड़े।

यह घटनाक्रम बताता है कि भारतीय बाजार को लेकर फुलाया गया गुब्बारा अब फूट चुका है। कुछ समय पहले ये गौरतलब खबर आई थी कि जियो हॉटस्टार आईसीसी के साथ अपने क्रिकेट प्रसारण समझौतों पर फिर से सौदेबाजी करना चाहता है। इसका कारण है कि मीडिया अधिकार पाने की लागत बहुत अधिक (138 करोड़ रुपये प्रति मैच) पड़ी है, जबकि विज्ञापन राजस्व उतना नहीं है। आम समझ है कि अगले साल जब फिर से मीडिया अधिकार बिकेंगे, तो आईसीसी को पहले से कम भाव पर ये बिक्री करनी होगी। तो कुल मिला कर सिर्फ आईपीएल हॉट प्रोपर्टी बना हुआ है, हालांकि इस वर्ष उसकी टीवी दर्शक संख्या पर भी सवाल खड़े हुए हैं।

एक लाख शिक्षकों की पेंशन पर छाया संकट, शासन के आदेश को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती

आंदोलन, हड़ताल, घेराव, ज्ञापन और न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से लगातार यह मांग उठाई जाती रही है, वर्तमान आदेश में केवल पहले से लागू संविलियन संबंधी प्रावधानों को दोहराया गया

नई दृष्टिबिंदु / कबीरधाम

संविलियन पूर्व सेवा अवधि को पेंशन में शामिल किए जाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के शिक्षक संगठनों ने एक बार फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में जारी आदेश में याचिकाकर्ता शिक्षकों के अभ्यावेदनों को अमान्य किए जाने पर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे उच्च न्यायालय के निर्देशों की मूल भावना के विपरीत बताया है।

एसोसिएशन का आरोप है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 9 जून 2026 को जारी आदेश में वर्ष 2021 के डब्ल्यूपीएस क्रमांक 777, 5699 और 2255 (रमेश चंद्रवंशी एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की सही व्याख्या किए बिना शिक्षकों के अभ्यावेदन निरस्त कर दिए हैं।

एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉ. रमेश कुमार चन्द्रवंशी ने कहा कि यदि शासन वास्तव में न्यायालय की भावना के अनुरूप निर्णय लेता, तो संविलियन पूर्व सेवा अवधि को पेंशन योग्य सेवा मानते हुए स्पष्ट आदेश जारी करता। उन्होंने कहा कि वर्तमान आदेश में केवल पहले से लागू संविलियन संबंधी प्रावधानों को दोहराया गया है, जबकि मूल विवाद संविलियन पूर्व सेवा को पेंशन में शामिल करने का है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1998 से 2018 के बीच नियुक्त एक लाख से अधिक शिक्षक पूर्व सेवा अवधि के पेंशन लाभ से वंचित हैं। इसके कारण कई शिक्षक बिना पेंशन के सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जबकि आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में शिक्षकों को केवल आंशिक पेंशन का लाभ मिलने की आशंका है।

एसोसिएशन के अनुसार, पेंशन की यह लड़ाई लंबे समय से जारी है। आंदोलन, हड़ताल, घेराव, ज्ञापन और न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से लगातार यह मांग उठाई जाती रही है। संगठन का कहना है कि उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में संविलियन पूर्व सेवा को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करने, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के सिद्धांतों का पालन करने तथा पेंशन को कर्मचारियों का अधिकार मानने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टिप्पणियां की हैं।

संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि शासन ने क्रमोन्नति संबंधी वर्ष 2026 की रिट अपील क्रमांक 191 और अन्य भिन्न मामलों के निर्णयों का हवाला देकर पेंशन संबंधी अभ्यावेदन खारिज किए हैं, जबकि इन मामलों का पेंशन विवाद से सीधा संबंध नहीं है। एसोसिएशन की प्रांतीय इकाई ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कानूनी परामर्श लेना शुरू कर दिया है और जल्द ही सक्षम न्यायालय में शासन के आदेश को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। संगठन का कहना है कि यह लड़ाई केवल कुछ याचिकाकर्ताओं की नहीं, बल्कि हजारों शिक्षकों के भविष्य और सम्मानजनक सेवानिवृत्ति से जुड़ा मुद्दा है।

खास खबर

अफीम-गांजा की खेती पर बढ़ेगी निगरानी

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले को नशामुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। कलेक्टर ने अधिकारियों को अफीम, गांजा, तंबाकू सहित अन्य मादक पदार्थों की अवैध खेती पर विशेष नजर रखने तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त वाहनों की राजसात और नीलामी की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय नारकोटिक्स समन्वय समिति (एनसीओआरडी) की बैठक में कलेक्टर ने मादक पदार्थों की अवैध खेती, तस्करी, नशा मुक्ति और प्रवर्तन संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व, वन और पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा कि मैदानी अमले को अफीम, गांजा और अन्य प्रतिबंधित फसलों की पहचान संबंधी जानकारी एवं तस्वीरें उपलब्ध कराई जाएं, ताकि अवैध खेती की समय रहते पहचान कर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। बैठक में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जब्त वाहनों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को राजसात और नीलामी की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा सभी मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

नशा मुक्ति और पुर्नवास सेवाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने पुर्नवास केंद्रों की क्षमता बढ़ाने, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और अधिक से अधिक प्रभावित लोगों तक उपचार एवं परामर्श सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया। औषधि नियंत्रण विभाग को लाइसेंस प्राप्त मेडिकल दुकानों एवं संस्थानों में नियंत्रित दवाओं के स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन करने तथा किसी भी अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

संबलपुर से अवैध खाद ला रहा ट्रक राजनांदगांव में जब्त, बिना दस्तावेज 197 बैग उर्वरक बरामद

राजनांदगांव। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देश पर उर्वरकों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। संबलपुर ओडिशा से अवैध रूप से खाद ला रहे ट्रक को जब्त कर पुलिस थाना सोमनी को सौंपा गया।

परसबोड़ में खड़े ट्रक की जांच : कृषि विभाग की टीम ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम परसबोड़ में खड़े ट्रक क्रमांक ओडी 17 एस 7676 की जांच की। ट्रक में बायो पोटाश के 37 बैग और ग्रो सुपर दानेदार के 160 बैग कुल 197 बैग खाद बिना वैध दस्तावेजों के पाए गए।

ओडिशा से लाकर राजनांदगांव में खाली करने की थी योजना : पूछताछ में ट्रक चालक ने बताया कि खाद संबलपुर ओडिशा से लेकर राजनांदगांव में खाली की जानी थी। कृषि विभाग ने खाद से भरे ट्रक को जब्त कर कार्रवाई की। विभाग लगातार निजी और सहकारी क्षेत्रों में निरीक्षण कर किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

कांग्रेसियों ने किया बेमेतरा कलेक्ट्रेट का घेराव समस्या व 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

घेराव के दौरान किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

किसानों की विभिन्न समस्याओं और 9 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को किसान कांग्रेस के नेतृत्व में बेमेतरा कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार पर भारी पुलिस बल तैनात किया था। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही बैरिकेड्स लगाए गए थे। इसके बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। घेराव के दौरान किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि खरीफ सीजन की शुरुआत के बावजूद किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। वहीं, डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों ने खेती की लागत को काफी बढ़ा दिया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और कमजोर हो रही है। इसके अलावा सिंचाई व्यवस्था की बदहाली, कृषि कार्यों में आ रही परेशानियों और किसानों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलने का मुद्दा भी प्रदर्शन के केंद्र में रहा।

मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहें किसान

कांग्रेस जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि प्रदेश का अन्नदाता आज अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। राज्य सरकार किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के बजाय केवल घोषणाएं करने तक सीमित है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के अधिकार, सम्मान और हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी किसानों की हर लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंने प्रशासन से किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द आवश्यक कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन के बाद किसान कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 9 सूत्रीय मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, अभिषेक मिश्रा, मंगत साहू समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

किसान चैतराम ने कहा नैनो उर्वरकों से मिला सकारात्मक परिणाम, कम लागत में हो रहा अधिक उत्पादन

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया जैसे उन्नत उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों को कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिल रही है। सहकारी समितियों के माध्यम से खादए बीज एवं कृषि आदान राशि की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने से किसान नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

जिले के विकासखंड मोहला अंतर्गत ग्राम झरन के प्रगतिशील कृषक चैतराम भी ऐसे ही किसानों में शामिल हैं, जो आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती को अधिक उन्नत और लाभकारी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 16 एकड़ कृषि भूमि में धान की खेती करने वाले चौतराम का परिवार लंबे समय से कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ है। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ उन्होंने अपनी खेती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में सहकारी समिति से खादए बीज एवं अन्य आवश्यक कृषि सामग्री प्राप्त करने पहुंचे चौतराम ने नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया भी लिया। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग एवं सहकारी समिति के माध्यम से उन्हें इन उर्वरकों की जानकारी मिली थी। पिछले वर्ष उन्होंने अपनी फसलों में नैनो उर्वरकों का उपयोग किया था, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। इससे फसल की वृद्धि बेहतर हुई और उत्पादन क्षमता में भी सुधार देखने को मिला।

चौतराम के अनुसार वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया किसानों के लिए एक प्रभावी और नवाचारपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, जो फसलों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके बेहतर अवशोषण में भी सहायक हैं। उन्होंने बताया कि इन उर्वरकों के उपयोग से फसलों को संतुलित पोषण मिलता हैए जिससे उनकी वृद्धि एवं विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

उन्होंने कहा कि किसानों के बीच नैनो उर्वरकों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और अधिक से अधिक किसान इनके उपयोग में रुचि दिखा रहे हैं। आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने से खेती अधिक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और लाभकारी बन रही है। साथ हीए समय पर खाद एवं बीज की उपलब्धता किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष उन्हें सहकारी समिति में आवश्यक कृषि सामग्री आसानी से उपलब्ध हो गईए जिससे खेती की तैयारी समय पर पूरी करने में मदद मिली।

जनसमस्या निवारण शिविर में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांग पुनीत के चेहरे पर आई मुस्कान

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत आज नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी स्थित कृषि मंडी परिसर में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 10, 11, 12, 13 एवं 14 के बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। यह जिले के नगरीय क्षेत्र में आयोजित होने वाला अंतिम शिविर था, जिसमें आमजनों की समस्याओं के निराकरण के साथ.साथ विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ भी हितग्राहियों को प्रदान किया गया।

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इसी क्रम में शिविर में दिव्यांग हितग्राही पुनीत राम को जनप्रतिनिधियों के हाथों मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। ट्राईसाइकिल प्राप्त करते ही उनके चेहरे पर खुशी और संतोष की मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने शासन एवं प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सहायता से उनके दैनिक जीवन में काफी सुविधा होगी। यह पहल सुशासन तिहार के वास्तविक उद्देश्य को सार्थक करता नजर आया।

शिविर की विशेष थीम स्वच्छ नगर, स्वस्थ जीवन, जिम्मेदार नागरिक रही। इस अवसर पर स्वच्छता, स्वास्थ्य जागरूकता तथा नागरिक कर्तव्यों के प्रति लोगों को प्रेरित किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित सुशासन तिहार 2026 शासन और जनता के बीच सीधे संवाद का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव, द्वार-द्वार सुशासन सरकार की भावना के अनुरूप

शासन-प्रशासन द्वारा गांवों और शहरों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत आयोजित शिविर आम नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं, जानकारी और योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने शिविर की थीम के अनुरूप स्वच्छता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल शासन या नगर निकाय की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। उन्होंने नागरिकों से अपने घरए मोहल्ले और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखनेए कचरे का उचित प्रबंधन करने तथा स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है और जनसहभागिता से ही स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मौके पर कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।

शिविर में जनपद अध्यक्ष पुनाऊ राम फुलकावरे, नगर पंचायत उपाध्यक्ष पवन गुप्ता, पार्षद श्रीमती ईश्वरी धुर्वे, पार्षद किसुन पटेल, पार्षद काशीराम निषाद, जनप्रतिनिधि आशीष द्विवेदी, गुलाब गोस्वामी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

सालभर पहले बेचा ढाई लाख का धान, अब तक नहीं मिला भुगतान

पीड़ित किसानों ने मुरारी ट्रेडर्स के खिलाफ कलेक्टर से की शिकायत

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

बांधाबाजार स्थित मुरारी ट्रेडर्स के पास करीब एक साल पहले धान बेचने वाले किसानों को अब तक भुगतान नहीं मिला है। पीड़ित किसानों ने संचालक मुरारी लाल खंडेलवाल के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राशि दिलाने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

2.65 लाख का धान बेचा, भुगतान नहीं

कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में कृषक लोमश पटेल, अशोक, अखिलेश, सीयाराम, मुकेश और सत्तार ने बताया कि उन्होंने मुरारी ट्रेडर्स के प्रो. मुरारी खंडेलवाल के पास धान बेचा था। लोमश पटेल ने 110 क्विंटल, अशोक, अखिलेश, सीयाराम ने 202 क्विंटल, मुकेश ने 144 क्विंटल और सत्तार ने 150 क्विंटल धान बेचा। कुल अनुमानित कीमत 2,65,500 रुपये है।

गबन कर फरार होने की आशंका

किसानों का कहना है कि मुरारी ट्रेडर्स का मंडी लाइसेंस होने के कारण धान बेचा गया, लेकिन व्यापारी ने छल और धोखा कर राशि नहीं दी। व्यापारी राजस्थान का मूल निवासी है। किसानों को आशंका है कि वह राशि का गबन कर फरार हो सकता है। पीड़ित किसान चेतन लाल साहू, लोमस राम और मुकेश कुमार चंदेल ने भी कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस प्रवक्ता बोले : संपत्ति कुर्क कर राशि दिलाई जाए

छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे ने कहा कि एक वर्ष तक भुगतान न करना अक्षम्य अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर संपत्ति कुर्क करते हुए किसानों को राशि दिलाई जानी चाहिए। उन्होंने मंडी लाइसेंस के तहत धान क्रय-विक्रय पंजी की जांच की भी मांग की।

कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

कलेक्टर जितेंद्र यादव ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। किसानों ने कहा कि खरीफ फसल के लिए उन्हें धनराशि की जरूरत है।

डोंगरगढ़ में राज्य स्तरीय वुशु स्पर्धा का हुआ आयोजन दुर्ग-भिलाई के 60 बच्चों ने जीते पदक

नई दृष्टिबिंदु / डोंगरगढ़-भिलाई

20 से 25 मई तक सेंट विन्सेंट डोंगरगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में दुर्ग-भिलाई के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। फुल कांटेक्ट स्पर्धा में दुर्ग-भिलाई के 60 बच्चों ने हिस्सा लिया और लगभग सभी ने पदक जीतकर इस्पात नगरी का नाम रोशन किया।

पदक विजेताओं का हुआ सम्मान

भिलाई के पदक विजेता बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा भिलाई जिला उपाध्यक्ष एवं सेक्टर-7 इस्पात क्लब के सचिव चिन्ना केशवलु ने बच्चों को मेडल पहनाए, पुष्प गुच्छ भेंट किए और मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया।

आगे बढ़ने का दिया मंत्र : चिन्ना केशवलु ने बच्चों को खेल में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दिया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने सभी प्रशिक्षकों को भी बधाई और शुभकामनाएं दीं। बच्चों की इस उपलब्धि से भिलाई में खुशी का माहौल है।

दर्शक अब सिर्फ एक्शन नहीं, रोल्स को भी महसूस करना चाहता है

अदिवि शेष इन दिनों अपनी एक्शन-ड्रामा फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' को लेकर चर्चा में हैं। 'क्षणम', 'गूढ़ाचारी' और 'मेजर' जैसी फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बना चुके शेष ने इस फिल्म के माध्यम से एक बार फिर दर्शकों के सामने नई कहानी पेश करने की तैयारी की है। दैनिक भास्कर के साथ इस विशेष बातचीत में अदिवि शेष ने अपनी आगामी से अपने जुड़ाव और इसके अन्य पहलुओं पर चर्चा की। मेरे लिए 'डकैत' का उद्देश्य केवल एक्शन दिखाना नहीं था 'डकैत' मूल रूप से सबसे पहले एक प्रेम कहानी है। मैं हमेशा इसे इसी तरह देखता हूं कि यह प्यार की कहानी में बुना गया एक्शन है, न कि एक्शन की कहानी में जोड़ा गया प्यार। अगर आपने फिल्म का गाना 'रूबरू' सुना है, जिसे फहीम अब्दुल्ला ने आवाज दी है, तो उसमें एक बेहद सादगी भरा, रूहानी और पुराने दौर के प्रेम का एहसास मिलता है। यह वैसी ही भावनाओं को दर्शाता है, जैसा कभी पुराने उपन्यासों या पिछली पीढ़ियों की प्रेम कहानियों में देखने को मिलता था। फिल्म का मूल विचार यही था कि जब इतने सरल, पवित्र और भावनात्मक प्रेम के बीच अचानक हिंसा और तीव्र एक्शन प्रवेश करता है, तो पूरा परिवेश किस तरह बदलता है। यही विरोधाभास इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। मेरे लिए 'डकैत' का उद्देश्य केवल एक्शन दिखाना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि भावनात्मक रूप से गहरे रिश्तों के बीच संघर्ष और हिंसा किस तरह असर डालते हैं। यही तत्व फिल्म को अलग, बड़े कैनवास वाली और विश्वसनीय बनाते हैं।

मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिले, तो मैं जर्मन भाषा में भी फिल्म कर लूंगा

मेरा नजरिया हमेशा से स्पष्ट रहा है। मैंने तब भी कहा था कि अगर मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिले, तो मैं जर्मन भाषा में भी फिल्म करने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए भाषा नहीं, बल्कि कहानी महत्वपूर्ण है। 'मेजर' के बाद मुझे हिंदी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री से 4-5 बड़ी वॉर फिल्में और बायोपिक्स ऑफर हुई थीं, लेकिन मेरे भीतर का लेखक मुझे बार-बार रोक रहा था। मुझे लगा कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभाने के तुरंत बाद किसी दूसरी सैनिक-आधारित कहानी का हिस्सा बनना सही नहीं होगा। मैं उनके माता-पिता की भावनाओं और उनकी यादों के प्रति ईमानदार रहना चाहता था। मेरे लिए हमेशा वही कहानी मायने रखती है, जो भीतर तक प्रभावित करे।

भारत भाग्य विधाता में अपने किरदार को लेकर कंगना ने की खुलकर बात

कंगना रनौत की आगामी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल में घटी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह फिल्म नर्स की बहादुरी की अनसुनी कहानी को बताती है। इस फिल्म में कंगना ने एक नर्स की भूमिका निभाई है। अपनी फिल्म और अपने किरदार को लेकर कंगना ने कई बातों का खुलासा किया है।

नर्स की ड्रेस को लेकर कंगना की राय

अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में एक नर्स की भूमिका निभाई है। एएनआई से बातचीत के दौरान इस फिल्म में नर्स की ड्रेस को लेकर कंगना ने कहा, 'नर्सों की वर्दी बहुत ब्रिटिश लगती है, उन्हें नर्सों की अपनी पसंद के अनुसार भारतीय रूप दिया जाना चाहिए।'

निभाई नर्स की भूमिका?

कंगना रनौत ने बताया कि उन्होंने 'भारत भाग्य विधाता' में एक नर्स की भूमिका क्यों निभाई है। कंगना ने कहा, 'अस्पताल के कर्मचारियों ने देश के लिए दृढ़ता दिखाई। एक नर्स अजमल कसाब की पहचान करने में महत्वपूर्ण गवाह बनकर उभरीं।' इसके साथ ही कंगना ने पीएम मोदी की 'भारत भाग्य विधाता' की योजना के बारे में भी खास बात बताई है।

'नर्सों ने 20 बच्चों को जन्म देने में की मदद'

कंगना रनौत ने कहा, 'भारत भाग्य विधाता 26/11 हमलों की एक अनकही वीरता की कहानी है।' इसके साथ ही कंगना ने बताया कि उस दौरान गोलियों और अफरा-तफरी के बीच, नर्सों ने 20 बच्चों को जन्म देने में मदद की थी।' फिल्म में कंगना रनौत ने एक नर्स की भूमिका निभाई है। उनके साथ गिरिजा ओक भी एक नर्स के किरदार में हैं। इस फिल्म को मनोज तापड़िया ने लिखा और निर्देशित किया है। 'भारत भाग्य विधाता' एक पैन-इंडिया फिल्म है। कंगना इस फिल्म की निर्माता भी हैं। कंगना और गिरिजा के अलावा फिल्म में स्मिता तांबे, सुहिता थाटे, आशा शेलार, प्रिया बेर्डे, ईशा डे, रसिका अधासे, अमृता नामदेव, आदित्य मिश्रा और जाहिद खान भी अहम किरदारों में हैं।

विवाद और आलोचनाओं के बाद 'पेद्दी' से हटाए गए जान्हवी कपूर के रोमांटिक सीन

राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म की तारीफ हो रही हैं। मगर, साथ ही आलोचनाएं भी हो रही हैं। फिल्म में जान्हवी कपूर को जिस तरह दिखाया गया है, उस पर विवाद शुरू हो गया। 'पेद्दी' में अभिनेत्री के कुछ गैर-जरूरी और बेहद बोल्ड सीन हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर निर्देशक और मेकर्स को ट्रोल किया गया।

क्यों लिया जान्हवी के सीन हटाने का फैसला

निर्देशक बुची बाबू सना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि जान्हवी कपूर के रोल को लेकर हुई आलोचना के बाद उन्होंने आखिरकार 'पेद्दी' से विवादित सीन हटा दिए हैं। यह कदम उन शॉट्स और रोमांटिक सीन पर आपत्तियों के बाद उठाया गया, जिन्हें महिलाओं के प्रति अपमानजनक माना गया था। निर्देशक ने कहा कि जान्हवी कपूर को बहुत ज्यादा बोल्ड दिखाने वाले हिस्सों पर सोशल मीडिया पर हुए हंगामे के बाद उन्होंने 'पेद्दी' से कुछ सीन हटा दिए हैं। निर्देशक बुची बाबू ने 'इंडियन एक्सप्रेस' के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि जान्हवी वाले कुछ सीन को लेकर गलतफहमी बढ़ गई थी। जान्हवी के किरदार 'अचियम्मा' को कई लोगों ने गलत समझा। दर्शकों ने 'अचियम्मा' के किरदार को लिखे जाने के तरीके पर सवाल उठाए थे। एक हिस्से और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों ने फिल्म के रोमांटिक ट्रैक की आलोचना की थी। इसके बाद मेकर्स ने एलान किया कि महिलाओं के प्रति अपमानजनक माने जाने वाले दृश्यों को काट दिया जाएगा।

बुची बाबू को मांगनी पड़ी माफी

विरोध बढ़ने पर बुची बाबू सना ने उन सीन को लेकर माफी मांगी और कहा कि उन्हें फिल्म से हटा दिया जाएगा। राम चरण और जान्हवी कपूर में से किसी ने भी अभी तक इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बुची बाबू ने कहा, 'मेरी राय में बहुत से लोगों ने जान्हवी कपूर के ट्रैक को एक अच्छी कहानी में अनावश्यक समझ लिया। उन्होंने कहा कि अपनी पिछली फिल्म के विपरीत 'पेद्दी' में उनका नजरिया जानबूझकर अलग रखा गया था। उनके अनुसार, मकसद राम चरण के किरदार 'पेद्दी' और उसके बदलाव के बीच अंतर दिखाना था। इस बदलाव की कहानी का एक हिस्सा जान्हवी के किरदार पर निर्भर था।

निर्देशक ने माना कि गलती हुई

बुची बाबू ने यह भी माना कि कुछ जगहों पर फिल्म बनाने के तरीके में गड़बड़ हुई। उन्होंने कहा, 'इस प्रक्रिया में कुछ शॉट्स ऐसे बन गए, जो गलत संदेश दे सकते थे। हमने उन्हें ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठाए और उन्हें हटा दिया। जिन दृश्यों की आलोचना हुई, उनमें जान्हवी का इंट्रोडक्शन शॉट भी शामिल था। जान्हवी के जिन सीन पर आपत्ति हुई है, उनमें एक वह सीन भी शामिल है, जिसमें राम चरण का किरदार पेद्दी, जान्हवी की मर्जी के बिना उसे किस करता है और कहता है कि उसे प्यार जाहिर करने का कोई और तरीका नहीं पता।

ट्रोलर्स की बातों से अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है

नागा चैतन्य के साथ रिश्ते और शादी को लेकर लंबे समय से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना कर रहीं शोभिता धुलिपाला ने आखिरकार आलोचकों को करारा जवाब दिया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 'अब मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी के बेहद खूबसूरत दौर में हूं।' बता दें कि शोभिता और नागा चैतन्य के रिश्ते की चर्चा साल 2022 में शुरू हुई थी। इसके बाद अगस्त 2024 में दोनों ने सगाई की और उसी साल दिसंबर में शादी कर ली। हालांकि, इस रिश्ते को लेकर शोभिता को लगातार सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। शोभिता ने आगे कहा कि 'लोगों की दिलचस्पी और चर्चाओं को मैं उत्सुकता के तौर पर देखती हूं। मैं बस अपनी जिंदगी जी रही थी और मुझे समझ नहीं आता कि लोग मुझसे कैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं। समय के साथ मुझे अपनी पहचान और मानसिक मजबूती का बेहतर एहसास हो गया है।'

अल्लू अर्जुन ने राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' पर दी प्रतिक्रिया

फिल्म 'पेद्दी' 04 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसमें रामचरण, जान्हवी कपूर और जगपति बाबू अहम भूमिकाओं में हैं। बॉक्स ऑफिस पर यह अच्छा कलेक्शन जुटा रही है। मगर, फिल्म में जान्हवी कपूर को अपनी भूमिका के लिए काफी ट्रोल किया गया है। इस बीच अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म पर अपने विचार रखे हैं।

अल्लू अर्जुन ने 'पेद्दी' पर क्या कहा

अल्लू अर्जुन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म 'पेद्दी' को लेकर पोस्ट की है। उन्होंने राम चरण, जगपति बाबू सहित पूरी टीम की तारीफ की है। एक तरफ उन्होंने राम चरण की भर-भरकर सराहना की है। निर्देशक बुची बाबू सना की भी पीठ थपथपाई है। वहीं, जान्हवी को लेकर खास कुछ नहीं लिखा, सिर्फ शुभकामनाएं दी हैं।

राम चरण के काम ने जीता दिल

अल्लू अर्जुन ने लिखा है, 'कल रात 'पेद्दी' देखी। मेरे प्यारे राम चरण की कमाल की परफॉर्मेंस है। दमदार और रॉ। कमाल का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। उस पर शानदार डांस मूव्स। उन्होंने हर मामले में कमाल कर दिया। वाकई। मुझे अपने भाई पर बहुत गर्व है। वह हर तारीफ के हकदार हैं। वहीं, जान्हवी को लेकर लिखा है, 'लीड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर को खूब सारा प्यार'। आगे लिखा है, 'जगपति बाबू गारू और बाकी सभी कलाकारों का काम भी शानदार है। सभी टेक्नीशियनों और निर्माताओं को बधाई। फिल्म के कैप्टन, बुची बाबू गारू को बहुत-बहुत बधाई, जिन्होंने सभी का स्तर बढ़ाया और राम चरण गारू को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया। 'पेद्दी' की पूरी टीम को बधाई। फिल्म 'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। सैकनिल्क पर प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, अब तक फिल्म ने 169.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है।

छोटे पर्दे की 'शोमैन' एकता कपूर: टैलेंट पहचानने से ट्रेंड बनाने तक, तीन दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर राज

भारतीय टेलीविजन की बात हो और एकता कपूर का नाम न आए, ऐसा शायद ही कभी हो। पिछले तीन दशकों में अगर किसी एक शख्स ने छोटे पर्दे की दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, तो वह हैं एकता कपूर। उन्हें यूं ही 'कंटेंट क्वीन' नहीं कहा जाता। उन्होंने सिर्फ टीवी शो नहीं बनाए, बल्कि ऐसे किरदार, कहानियां और ट्रेंड्स गढ़े जो लोगों की जिंदगी और बातचीत का हिस्सा बन गए।

कपूर ने उस दौर में टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा, जब मनोरंजन के विकल्प बेहद सीमित थे लेकिन उन्होंने भारतीय दर्शकों की नब्ज को जिस तरह समझा, उसने उन्हें बाकी निर्माताओं से अलग खड़ा कर दिया। उनकी कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स ने भारतीय टेलीविजन को ऐसे शो दिए, जिन्होंने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और घर-घर में अपनी पहचान बनाई। एकता कपूर के धारावाहिकों के किरदार इतने लोकप्रिय हुए कि लोग उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मिहिर विरानी की मौत। यह सिर्फ एक कहानी का मोड़ नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय घटना बन गई थी। दर्शकों ने विरोध किया, भावुक हुए और आखिरकार शो के निर्माताओं को मिहिर को वापस लाना पड़ा। यह भारतीय टेलीविजन के इतिहास के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गया।

इसी तरह 'कसौटी जिंदगी की' की कोमोलिका को कौन भूल सकता है? उर्वशी ढोलकिया का यह किरदार सिर्फ एक खलनायिका का नहीं था, बल्कि एक पॉप कल्चर आइकॉन बन गया। उनकी स्टाइलिश बिंदी, ड्रामैटिक एंट्री और बैकग्राउंड म्यूजिक ने ऐसा असर छोड़ा कि आज भी कोमोलिका का नाम लेते ही वह छवि आंखों के सामने आ जाती है।

एकता कपूर ने सिर्फ ड्रामा नहीं रचा, बल्कि ट्रेंड भी बनाए। 'कुटुंब' और 'कहीं तो होगा' जैसे शोज ने रोमांस को नए अंदाज में पेश किया। ऑफिस रोमांस की कहानियों ने युवाओं के बीच एक नया क्रेज पैदा किया। वहीं 'नागिन' के जरिए उन्होंने सुपरनेचुरल फिक्शन को मुख्यधारा में ला खड़ा किया। मौनी रॉय का इच्छाधारी नागिन वाला किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि यह शो भारतीय टेलीविजन की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में शामिल हो गया।

एकता कपूर की सफलता सिर्फ उनके शोज तक सीमित नहीं है। उन्हें इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन 'टैलेंट स्पॉटर' भी माना जाता है। उन्होंने कई ऐसे कलाकारों को मौका दिया, जो आगे चलकर बड़े सितारे बने। विद्या बालन को शुरुआती पहचान 'हम पांच' से मिली। आज वही विद्या भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को भी घर-घर तक पहुंचाने का श्रेय काफी हद तक एकता कपूर को जाता है। 'पवित्र रिश्ता' के मानव के रूप में उन्होंने करोड़ों दर्शकों का दिल जीता और यहीं से उनके फिल्मी करियर की मजबूत नींव पड़ी। इसी तरह मौनी रॉय, प्राची देसाई, अनीता हसनंदानी, राधिका मदान और कई अन्य कलाकारों कोभी एकता कपूर के मंच से पहचान मिली। यही वजह है कि इंडस्ट्री में उन्हें सिर्फ निर्माता नहीं, बल्कि 'स्टारमेकर' भी कहा जाता है।

एकता कपूर की एक और खासियत यह रही कि उन्होंने समय के साथ खुद को लगातार बदला। जब टीवी का दौर चरम पर था, तब उन्होंने छोटे पर्दे पर राज किया और जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दौर आया तो उन्होंने वेब कंटेंट की दुनिया में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। वह दर्शकों की बदलते पसंद को समझती रही और उसी के अनुसार कंटेंट तैयार करती रही।

उनकी मेहनत और योगदान को देश-दुनिया में कई बड़े सम्मान मिले हैं। पद्म श्री के साथ ही एकता कपूर को बिजनेस, मीडिया और मनोरंजन जगत के कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है।

अनियमित बिजली कटौती से लोग हलाकान, भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जताया आक्रोश

अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने अधीक्षण यंत्री को सौंपा ज्ञापन, कई समस्याएं बताई, समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग, जनआंदोलन की चेतावनी भी

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

लगातार अनियमित बिजली कटौती से लोगों को हो रही परेशानियों को भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने गंभीरता से लिया है। अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार, 11 जून को सीएसईबी के अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन सौंप इस घोषित बिजली कटौती को तत्काल बंद किए जाने की मांग की। साथ ही स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्या,मीटर रीडरो के बेरोजगार होने, मेंटेनेंस के नाम पर खानापूर्ति करने आदि समस्यायों के तत्काल निदान की मांग की गई। ज्ञापन में चेतावनी भी दी गई है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो जनता के हित में व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा।

ज्ञापन सौंपते हुए अध्यक्ष श्री चंद्राकर ने अधिकारियों को बताया कि मानसून पूर्व संधारण कार्य के नाम पर बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित की जा रही है। मेंटेनेंस के बावजूद पहली ही बारिश में विद्युत व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने आ जाती है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घंटों बिजली गुल रहने की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। विभाग को चाहिए कि वह संधारण कार्य को केवल औपचारिकता तक सीमित न रखकर गंभीरता एवं जवाबदेही के साथ पूरा करे, ताकि वर्षा ऋतु में आम जनता को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

अधीक्षण यंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि विद्युत वितरण कंपनी में आवश्यक स्पेयर पार्ट्स जैसे कट-आउट, इंसुलेटर, बस-बार सहित अन्य सामग्री की भारी कमी है। कई स्थानों पर ट्रांसफार्मरों के पास विद्युत पैनल खुले पड़े हैं, जो न केवल तकनीकी लापरवाही को दर्शाते हैं बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ाते हैं।

श्री चंद्राकर ने बताया कि स्मार्ट मीटर प्रणाली लागू होने के बाद लगभग 5000 मीटर रीडरों के समक्ष रोजगार का गंभीर संकट पैदा हो गया है। उन्होंने मांग की कि पिछले 20 वर्षों से विभाग के लिए सेवाएं दे रहे इन कमर्चारियों को मानवीय आधार पर विभाग में अन्य उपयुक्त कार्यों में समायोजित किया जाए ताकि उनके परिवारों की आजीविका प्रभावित न हो। उन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर आवश्यकता से अधिक पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो जनता के हित में व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने में विशेष रूप से मुकेश चंद्राकर, नरसिंह नाथ, जी राजू, सीजू एंथोनी, रविंदर सिंह, भूपेंद्र यादव, मोहम्मद रफीक, दर्शन सिंह, आनंद डोंगरे, जितेश बंजारे, गोविंद कोसले, शोएब, स्वप्निल जैन, दिनेश पटेल, अली हुसैन सिद्दीकी, उमा शंकर साहू, हीरा शंकर साहू, विनोद यादव, मेरिक सिंग, इमरान खान, जावेद खान, राजेश साहू, अजय यादव, लाल चंद वर्मा, प्रभाकर जनवंधु, राजेश चौधरी, शीर्षिज घोष, सोनू अंसारी, मनीष शुक्ला, फायाज अहमद, खानजी और अन्य साथी उपस्थित थे।

खास खबर

उर्स और दरगाहों में डीजे, नाच-गाने पर पाबंदी की मांग, वक्फ बोर्ड ने जारी किए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

जमात रजा ए मुस्तफा की शिकायत पर 50 हजार जुर्माना और जब्ती का प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रदेश की तमाम दरगाहों, उर्सों और मजहबी जलसों में डीजे, नाच-गाना, धुमाल और गैर-शरई कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने संभाग आयुक्त, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहा है। **जमात रजा ए मुस्तफा ने की थी शिकायत :** जमात रजा ए मुस्तफा, रायपुर ने 23 मई 2026 को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि प्रदेश की कई दरगाहों और उर्स के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाना, जुलूसों में नचनियों को बुलाकर फूहड़ कार्यक्रम करना कुरआन और हदीस के खिलाफ है। इससे सूफी संतों के आदेशों की अवहेलना हो रही है और समाज में गलत संदेश जा रहा है। **रात 11 बजे तक संदल-चादर, डीजे पर 50 हजार जुर्माना :** वक्फ बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि उर्स के अवसर पर संदल चादर का समय अंतिम रात 11 बजे तक निर्धारित किया जाए। संदल चादर में डीजे, धुमाल और आतिशबाजी प्रतिबंधित रहेगी। जो संस्था या व्यक्ति डीजे या धुमाल बुलवाएगा उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और डीजे-धुमाल जब्त किया जाएगा। **उर्स का उद्देश्य अमन और भाईचारा :** जमात ने पत्र में कहा कि उर्स का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, आपसी भाईचारा, सामाजिक समरसता और अमन-शांति का माहौल कायम रखना है। डीजे और नाच-गाने से उर्स की रूहानियत और अदब को नुकसान पहुंच रहा है। कुछ लोग उर्स को तमाशा और दिखावा बनाकर इसकी पवित्र फिजा प्रभावित कर रहे हैं। **इनको भेजी गई प्रति :** वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने यह पत्र राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, वक्फ बोर्ड के सभी सदस्यों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सभी दरगाहों की प्रबंध कमेटी और जमात रजा ए मुस्तफा को भेजा है। वक्फ बोर्ड ने सभी संबंधित अधिकारियों से शीघ्र कार्रवाई कर अवगत कराने को कहा है।

रायपुर में नारकोटिक्स नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्रीशीटर समेत 8 गिरफ्तार

रायपुर। पुलिस आयुक्त डॉ. संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में एण्टी क्राईम एण्ड साइबर यूनिट, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और थानों की संयुक्त टीम ने नारकोटिक्स के लोकल नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है। 96 घंटे के विशेष ऑपरेशन में हिस्ट्रीशीटर समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। टिकरापारा, सिविल लाइन, न्यू राजेन्द्र नगर, खमतराई और डीडी नगर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। आरोपियों के कब्जे से 8.75 ग्राम हेरोइन, 5 ग्राम एमडी, 1.8 किलो गांजा, 1.2 किलो गांजा, 198 नग नाईट्राजेपान टेबलेट और 40 नग प्रतिबंधित टेबलेट बरामद हुई। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 5 लाख रुपये है। **हिस्ट्रीशीटर अफसर कादर भी पकड़ा गया :** सिविल लाइन प्रकरण में गिरफ्तार अफसर कादर थाना मौदहापारा का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ रायपुर के विभिन्न थानों और नागपुर में हत्या का प्रयास, बलवा, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, ब्लैकमेलिंग, दुष्कर्म समेत 2 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं। **कमिश्नरेट में अब तक 113 गिरफ्तार :** पुलिस उपायुक्त (क्राइम) के अनुसार कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद नारकोटिक एक्ट के कुल 49 प्रकरणों में 113 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2.63 करोड़ रुपये से अधिक का मशरूका जब्त किया जा चुका है। सभी प्रकरणों में End To End विवेचना कर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। **गिरफ्तार आरोपी :** टिकरापारा से हरप्रीत सिंह मद्दू और ऋषि साहू, सिविल लाइन से अफसर कादर और मीर कुरैशी उर्फ विक्की, न्यू राजेन्द्र नगर से महावीर जैन, डीडी नगर से गुलाब कंडरा तथा खमतराई और सिविल लाइन से 2 विधि के साथ संघर्षरत बालकों को गिरफ्तार किया गया है।

गरीबों के आशियाने पर संकट, ढाल बनकर डटे वोरा कलेक्टर-आयुक्त से की टेलीफोन पर दो टूक चर्चा

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

प्रधानमंत्री आवास योजना (ढटअ) के अंतर्गत निर्मित गैलेक्सी हाइट्स आवासीय परिसर में उस समय तनाव की स्थिति निर्मित हो गई जब 252 आवासों में से लगभग 24 आवासों को खाली कराने के लिए पुलिस बल पहुंचने की सूचना सामने आई। कार्रवाई की खबर फैलते ही रहवासियों में भय और चिंता का माहौल बन गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दुर्ग के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण वोरा को मौके पर बुलाया।

सूचना मिलते ही अरुण वोरा अपने सहयोगियों के साथ गैलेक्सी हाइट्स पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान रहवासियों ने बताया कि वे वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के बजाय बेदखली की कार्रवाई की जा रही है।

रहवासियों ने आरोप लगाया कि पूरी कॉलोनी में पेयजल की गंभीर समस्या है। एकमात्र जल स्रोत के भरोसे सैकड़ों परिवार निर्भर हैं। जगह-जगह गंदगी फैली हुई है, नियमित सफाई व्यवस्था नहीं है तथा सफाई कर्मचारी महीने में केवल एक-दो बार ही पहुंचते हैं। कॉलोनी में हैंडपंप तक की व्यवस्था नहीं है। लोगों का कहना है कि दूषित पानी और अस्वच्छ वातावरण के कारण कई लोग पीलिया जैसी बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं तथा कुछ लोगों की मृत्यु होने की बात भी सामने आई है।

महिलाओं ने अरुण वोरा के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यहां रहने वाले अधिकांश परिवार मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उन्होंने कहा कि हम दिनभर मेहनत-मजदूरी करके घर चलाते हैं। सरकार को हमारी स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए। इतनी भीषण गर्मी में हम कहां जाएंगे? अब बारिश का मौसम भी सामने है। यदि हमें घरों से बेदखल कर दिया गया तो हमारे परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।

रहवासियों की पीड़ा सुनने के बाद अरुण वोरा ने मौके से ही कलेक्टर और आयुक्त से टेलीफोन पर चर्चा करते हुए मामले में संवेदनशीलता बरतने की मांग की। उन्होंने कहा कि—गैलेक्सी हाइट्स में रह रहे परिवार पहले से ही अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पेयजल, सफाई, बिजली और जलभराव जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। ऐसे में अचानक बेदखली की कार्रवाई उचित नहीं है। प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभावित परिवारों को पर्याप्त समय देना चाहिए, इन परिवारों द्वारा आवासों का भुगतान किया जा रहा है और शेष बकाया राशि का भुगतान भी वे कर देंगे।

सरकार की योजनाओं का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी पात्र परिवार के साथ अन्याय न हो। प्रशासन को समाधान निकालना चाहिए, दमनात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।मैं संबंधित अधिकारियों और आयुक्त से अपील करता हूं कि मामले का समाधान बातचीत और सहमति के माध्यम से निकाला जाए।

उन्होंने नगर निगम के स्थानीय प्रशासन विभाग की सचिव एस. संगीता से भी चर्चा कर निवासियों को राहत देने और लंबित मामलों के निराकरण तक बेदखली की कार्रवाई रोकने का आग्रह किया। इस दौरान पूर्व महापौर आरएन वर्मा, फतेह सिंह भाटिया एवं राजकुमार पाली भी उपस्थित थे। पूर्व महापौर आरएन वर्मा ने कहा कि प्रभावित परिवारों को निश्चित रूप से समय मिलना चाहिए ताकि वे अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकें। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को व्यावहारिक और मानवीय निर्णय लेना चाहिए।

परिवहन विभाग का अभियान, 350 वाहनों की जांच में वसूला जुर्माना

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने प्रदेशभर में विशेष जांच अभियान चलाया है। सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा को लेकर चलाए गए अभियान में अब तक 350 वाहनों की सघन जांच की गई है। नियम तोड़ने पर वाहन स्वामियों से 5.50 लाख रुपये का समन शुल्क वसूला गया है।

स्लीपर बसों पर विशेष नजर

परिवहन आयुक्त एस प्रकाश ने सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को यात्री बसों, विशेषकर स्लीपर कोच बसों की कड़ाई से जांच के निर्देश दिए हैं। स्लीपर बसों में चालक दल के लिए बनाए गए अनधिकृत पार्टीशन और स्लीपर बर्थ में लगे अवैध स्लाइडरों को मौके पर ही हटाया जा रहा है।

10 किलो के अग्निशमन यंत्र अनिवार्य

बसों में सुरक्षा के लिए न्यूनतम 10 किलोग्राम क्षमता के अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। जीपीएस की कार्यशीलता परखी जा रही है। मानकों के विपरीत बनी बस बॉडी के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। पंजीयन, फिटनेस, परमिट और एआईएस-119 मानकों के अनुरूप निर्माण की जांच की जा रही है।

लापरवाही पर कठोर कार्रवाई

परिवहन आयुक्त ने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। चालान, परमिट और लाइसेंस निलंबन जैसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

संचालकों को समझाइश

विभाग विभिन्न जिलों में बस स्वामियों और संचालकों की बैठकें ले रहा है। उन्हें तय नियमों और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों से समझौता करने वाले संचालक को बख्शा नहीं जाएगा।

महाशिवमहापुराण कथा : कर्म पर अधिकार है, फल भगवान शंकर देंगे-आचार्य विक्रांत

महाशिवपुराण कथा का हुआ समापन, उमड़ा आस्था का सैलाब

नई दृष्टिबिंदु / लिटिया-सेमरिया

सात दिवसीय शिव महापुराण कथा का शांतिपूर्ण समापन हुआ। अंतिम दिन दोपहर 2 से 5 बजे तक व्यास पीठ से आचार्य डॉ. विक्रांत दुबे ने प्रवचन दिया। कथा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए।

आचार्य ने कहा कि देवता भी रावण से डरते थे, लेकिन रावण केवल महादेव से भय खाता था। उन्होंने कहा कि कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल भगवान शंकर देंगे। समर्पण और निष्ठा से किया गया काम ही सच्चा कर्म है।

आचार्य ने कहा कि यह पृथ्वी लोक शंकर का है। देवलोक, इंद्रलोक और स्वगलीक में पुण्य समाप्त होने पर वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। यहां कंकड़-कंकड़ में शंकर बसे हैं। उन्होंने सभी से कैलाश पर्वत पर भगवान भोले के चरणों में रहने की कामना करने को कहा।

आचार्य ने बताया कि भगवान शिव को पालक और संहारक दोनों रूपों में पूजा जाता है। कोमल हृदय, दयालु और आसानी से माफ करने वाले होने के कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। शिव थोड़े से प्रयास से भी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सच्ची श्रद्धा से तुरंत वरदान देते हैं।

उन्होंने कहा कि शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से कई भगवान शिव को प्रिय हैं। विष को कंठ में धारण करने से वे नीलकंठ कहलाए। नंदी, नाग, चंद्रमा, मदार पुष्प, बेलपत्र, गंगा, त्रिशूल और डमरू भी समुद्र मंथन से जुड़े हैं। बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं।

कार्यक्रम में 11 वर्षीय सार्थक ललित शर्मा ने बाबा श्याम का मधुर गीत प्रस्तुत किया, जिस पर भक्त झूम उठे। कथा के बाद शाम 5 बजे हवन, पूर्णाहुति और आरती हुई। इसके बाद रामधुन के साथ शोभायात्रा निकाली गई। शाम 7 बजे पुड़ी, सब्जी, हलवा और बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया।

समय रहते रुका बाल विवाह, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य को मिला नया अवसर

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-सुकमा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन और बाल संरक्षण के संकल्प को साकार करते हुए सुकमा जिले में प्रशासन की तत्परता से एक 14 वर्षीय किशोरी का बाल विवाह रुकवाया गया। यह पहल न केवल एक बालिका के अधिकारों की रक्षा का उदाहरण बनी, बल्कि उसके बेहतर भविष्य और शिक्षा के मार्ग को भी सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। सुकमा जिले के दूरस्थ ग्राम कडयुपारा (मांडुपारा), सिरसेट्टी में एक 14 वर्षीय बालिका का विवाह 15 जून को प्रस्तावित था। बाल विवाह की सूचना मिलते ही कलेक्टर अमित कुमार के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम तत्काल गांव पहुंची।

स्थानीय सामाजिक परंपराओं के तहत नाबालिग बालिका का विवाह तय किया गया था और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी थीं। संयुक्त टीम ने बालिका, उसके परिजनों और ग्रामीणों से संवाद कर बाल विवाह के दुष्परिणामों, बाल अधिकारों तथा कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। अधिकारियों की संवेदनशील समझाइश और लगातार प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया। परिवार ने बाल विवाह स्थगित करने की सहमति दी और बालिका ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए बेहतर भविष्य बनाने की इच्छा व्यक्त की। इसके बाद प्रशासन ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए घोषणा पत्र और पंचनामा तैयार कराया।

यह कार्रवाई केवल एक बाल विवाह रोकने तक सीमित नहीं रही, बल्कि बाल संरक्षण और बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण बनी। प्रशासन, चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस विभाग और ग्राम पंचायत के समन्वित प्रयासों ने यह संदेश दिया कि बच्चों के अधिकार, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य सर्वोपरि हैं। समय पर हस्तक्षेप से एक किशोरी को कम उम्र में विवाह के बंधन में बंधने से बचाया गया और उसे अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिला। यह पहल समाज में जागरूकता बढ़ाने और बाल विवाह जैसी कुप्रथा के उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

इस अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन, पुलिस विभाग तथा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस कार्यवाही के दौरान सुश्री मनीषा शर्मा संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख), रविन्द्र घृतलहरे संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) सुश्री रश्मि चन्द्रवंशी सेक्टर सुपरवाइजर, जोगेंद्र दिर्दो सामाजिक कार्यकर्ता, मनोज एक्का चाइल्ड लाइन सुपरवाइजर, सुश्री अंजलि वेट्टी आउटरिच वर्कर, श्रीमती देवे मिश्रा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पुलिस विभाग से श्री सुमित तिर्की, सामनाथ नाग थाना केरलपाल, ग्राम सरपंच बुधरा पोडियामी एवं ग्राम सचिव जुबराज सरकार उपस्थित रहे। इन सभी के समन्वित प्रयासों से बालिका के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हुई और उसके उज्ज्वल भविष्य की राह प्रशस्त हुई।

धान खरीदी से बचने के लिए सरकार दे रही 15 हजार का प्रोत्साहन : किसान संगठन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्य सरकार के धान छोड़कर अन्य फसल लेने पर प्रति एकड़ 15 हजार रुपये देने के फैसले पर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने प्रतिक्रिया दी है। संगठन के संयोजक एड राजकुमार गुप्त ने कहा कि सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी करने से बचना चाहती है।

अर्थव्यवस्था पर बोझ का हवाला : एड गुप्त ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से धान खरीदी राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बन गया है। सरकार आर्थिक बोझ से छुटकारा पाने के लिए धान की उपज लेने से किसानों को हतोत्साहित कर रही है और अन्य फसल के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

रकबे में खास कमी नहीं आएगी : कसान संगठन के संयोजक ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से धान बेचने के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या और धान के रकबे में कोई खास कमी नहीं होने वाली है। उन्होंने मांग की कि खरीफ सीजन में धान को छोड़कर दलहन, तिलहन या अन्य उपज लेने वाले किसानों की फसल की एमएसपी पर सरकारी खरीद भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

तिकड़म से बचने की चेतावनी : एड गुप्त ने सरकार को आगाह किया कि धान की उपज लेने से हतोत्साहित करने के लिए तिकड़म का सहारा लेकर किसानों को परेशान न किया जाए। पिछले खरीफ सीजन की तरह दबाव और प्रताड़ना से बचा जाए। किसानों की सहमति से ही धान के स्थान पर अन्य फसल लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100